



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1987/ज्याइस्था 1, 1909

No. 276]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 1987/JYAISTHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 मई, 1987

अधिसूचना

सा० का० नि० 523(अ)—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद्रास पत्तन न्यास (पेंशन) विनियम, 1987 का अनुमोदन करती है।

उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं० पी.आर.-12018/9/86-पीई.1]

पी० एम० अशाहम, अपर सचिव

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पेंशन विनियम

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 (1963 का 38) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एतद्वारा निम्नलिखित मसौदा विनियम बनाता है, बशर्ते कि सरकारी मंजूरी मिल जाए तथा ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के मौजूदा पेंशन नियमों का अधिक्रमण करते हैं तथा ये इसमें प्रकाशित कराए जा रहे हैं जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत अपेक्षित है।

प्रारम्भिक अध्याय—1

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भण—(अ) ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पेंशन विनियम 1987 कहलाएंगे।

2. अनुप्रयोग—ये विनियम के लिए लागू होंगे :—

(अ) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पेंशन नियम से निगमित होने वाले कर्मचारियों के लिए।

(भा) भर्ती किए गए सभी व्यक्ति जिसमें नियुक्त किए गए सटीय श्रमिक भी शामिल हैं।

(इ) ऐसे अन्य कर्मचारी जिन्हें समय-समय पर पेंशन योजना को अपनाने की अनुमति दी जा सकती है।

3. परिभाषाएं—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो—

(अ) लेखा अधिकारी से तात्पर्य बोर्ड के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी से है, जिसे कि अध्यक्ष निर्धारित करें।

(आ) अधिनियम से तात्पर्य महा परतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) से है।

(इ) औसत परिलब्धियों से तात्पर्य विनियम 24 के अनुसार तय किए गए औसत।

(ई) बोर्ड, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष का वही अर्थ होगा जैसा कि उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

(उ) बच्चा से अर्थ है कर्मचारी का बच्चा जो यदि पुत्र है, तो 21 वर्ष से कम उम्र का हो, अगर पुत्री है, तो वह 24 वर्ष से कम उम्र की हो तथा गैर-शादीशुदा हो तथा सन्तानहीन बच्चों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(ऊ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तात्पर्य बोर्ड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से है।

(अ) परिस्थितियों से तात्पर्य विनियम 23 में निर्धारित की गई परिलब्धियों से है।

(ए) कर्मचारी स्थाई तथा अस्थायी कर्मचारी का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति पब्लिसिटी आदि) विनियमों में दिया गया है।

(ऐ) परिवार पेंशन से तात्पर्य कर्मचारी की मृत्यु अथवा उसके सेवानिवृत्त होने के बाद यथास्थिति उसके परिवार को देय पेंशन से है।

(ओ) विदेश सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है जिसमें कोई भी कर्मचारी सक्षम मंजूरी से मद्रास पोर्ट ट्रस्ट की निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से अपना वेतन प्राप्त करता है।

(औ) उपदान से तात्पर्य अध्याय 9 के तहत देय उपदान से है।

(अं) छुट्टी से तात्पर्य भारत सरकार के मौलिक नियम अथवा बोर्ड द्वारा बनाए गए छुट्टी विनियमों के द्वारा गणना की जाने वाली किसी भी प्रकार की छुट्टी है, जो समय-समय पर लागू होगी।

(अः) नाबालिग से तात्पर्य वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है।

(क) पेंशन में उपदान भी शामिल है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें पेंशन शब्द उपदान के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) अर्हक सेवा से तात्पर्य की गई ऐसी सेवा जो तैनाती के समय अथवा अन्यथा की गई हो तथा जिसकी इन विनियमों के तहत पेंशन तथा उपदान के प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी।

(ग) सेवानिवृत्त लाभ से तात्पर्य पेंशन तथा उपदान से है।

(घ) सेवा से तात्पर्य रोजगार में आने की दिनांक से इसके छोड़ने की दिनांक तक की सेवा की अवधि से है, जिसमें वैतनिक अथवा अवैतनिक छुट्टियों की अवधि भी शामिल है।

4. निम्नलिखित श्रेणियों के लिए पेंशन लागू होगी :—

1. निवर्तन पेंशन
2. सेवा निवृत्त पेंशन
3. असमर्थ पेंशन
4. मुआवजा पेंशन
5. अनुकम्पा भत्ता
6. अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन

5. निवर्तन पेंशन :—निवर्तन पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी करने के बाद सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

6. सेवानिवृत्ति पेंशन :—सेवानिवृत्ति पेंशन ऐसे कर्मचारियों को प्रदान की जाती है जो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्त) विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने की उम्र से पहले ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं अथवा सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

7. असमर्थ पेंशन :—(1) असमर्थ पेंशन उन कर्मचारियों को प्रदत्त की जाती है जिन्हें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के कारण सेवा से स्थाई रूप से असक्षम करार दिया जाता है।

(2) असमर्थ पेंशन का दावा प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से असक्षमता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) चिकित्सा प्रमाण-पत्र वह होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ऐसा कार्य जिसे वह कर रहा था उसके कुछ निम्न स्तर के कार्य करने के लिए सेवा में और अधिक समय तक रहने के लिए उपयुक्त घोषित किया है और वह कर्मचारी उस निम्न स्तर के कार्य करने के लिए तैयार है तो उसे निम्न स्तर वाले पद पर नियोजित किया जाएगा और उसे नियोजित करने का कोई निम्न स्तरवाला पद भी मौजूद न हो तो उसको असमर्थ पेंशन की स्वीकृति कर दी जाएगी।

(5) अगर असक्षमता का कर्मचारी के अनियमित या असयमी होने की आवृत्ति से सीधा सम्बन्ध है तो उसे असमर्थ पेंशन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(6.) अगर सक्षमता सीधे उक्त आदतों की वजह से नहीं हुई परन्तु इनके कारण इसे बढ़ावा मिला है अथवा ओर बढ़ाव हो गई तो उसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे कि इस नेखे में कितना कमी की जाएगी।

(8.) मुआवजा पेंशन:—अगर किसी कर्मचारी को उसके स्थाई पद के समाप्त करने के कारण उसे सेवा से निकालने के लिए चुना जाता है तथा जब तक कि उस दूसरे समकक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जाता तो वह निम्न विकल्प दे सकता है :—

1. उसके द्वारा पहले से ही की गई सेवा के लिए मुआवजा पेंशन स्वीकार करना जिसके लिए कि वह पात्र है। अथवा
2. ऐसे वेतन पर अन्य नियुक्ति स्वीकार करना जो कि दी जाए तथा अपनी पिछली सेवा की पेंशन के लिए जारी रखना।
3. अगर कोई व्यक्ति अन्य नियुक्ति की स्वीकार करने के बजाय हकदार पेंशन स्वीकार करता है तथा इसके पश्चात वह किसी भी श्रेणी का पेंशन का हकदार हो जाता है तो इस प्रकार की पेंशन मुआवजा पेंशन से कम नहीं होगी जिसका कि उसने दावा किया होता और अगर उसने अन्य नियुक्ति को स्वीकार न किया होता।

9. अनुकम्पा भत्ता :—अगर किसी की सेवा से बरखास्त या निष्कासित किया जाता है तो उसकी पेंशन जब्त हो जाएगी

परन्तु इस तरह बरखास्त या निष्कासित किए गये कर्मचारियों के ऐसे सुपात्र मामलों में अनुकम्पा भत्ता जो न्यूनतम वेतन से कम न हो तथा पेंशन के 2/3 भाग से अधिक न हो जैसा उसके अनुकम्पा पेंशन पर सेवानिवृत्त होने पर भुगतान किया जाता, प्रदान किया जाएगा।

10. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन :—अगर कोई कर्मचारी दण्डस्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाता है तो उसे पेंशन या उपदान या दोनों मुआवजा पेंशन के 2/3 भाग से कम न हो तथा उससे अधिक न हो, और जो सम्पूर्ण मुआवजा पेंशन या उपदान या दोनों से अधिक न हो जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय उसे प्राप्त होती इस शर्त पर कि इन विनियमों के तहत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती, का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय 3

11. पेंशन की पात्रता के लिए शर्तें :—पेंशन की हकदारी के लिए इन विनियमों के तहत किसी भी कर्मचारी को निम्न लिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

1. उसकी अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

2. सेवा मूल या स्थाई होनी चाहिए।

अध्याय 4 :—पेंशन के लिए अर्हक सेवा

12. अर्हक सेवा का प्रारम्भ होना :—1. कर्मचारी की अर्हक सेवा उस दिनांक से प्रारम्भ मानी जाएगी जिससे कि

वह प्रथम पद पर नियुक्त किया गया था चाहे मूल पद के रूप में या स्थानापन्न या अस्थायी रूप में।

बशर्ते कि स्थानापन्न अथवा अस्थायी सेवा जिसमें परि-वीक्षा समय भी शामिल है में उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से पद पर कार्य करने से उसके उसी पद स्थायी अथवा अन्य पद पर कार्य करने में कोई बाधा न हुई हो।

2. कर्मचारी द्वारा 18 वर्ष की उम्र के पूरे होने से पहले उसके द्वारा की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी।

3. आकस्मिक सेवा की गणना पेंशन के लिए नहीं की जाएगी।

13. शिक्षु की सेवा की गणना :—शिक्षु के रूप में की गई सेवा की गणना पेंशन के लिए नहीं की जाएगी।

14. पेंशन प्रयोजनार्थ छुट्टी की अवधि की गणना :—

सेवा के दौरान ली गई सभी छुट्टियों जिनके लिए छुट्टी वेतन का भुगतान किया गया है तथा सभी असाधारण छुट्टियों जो चिकित्सा आधार पर ली गई हैं पेंशन के लिए अर्हक सेवा में गिनी जायेंगी। बशर्ते कि असाधारण छुट्टियों के मामले में चिकित्सा आधार पर दी गई छुट्टियों के अलावा असाधारण छुट्टियों के मंजूर करते समय नियुक्ति प्राधिकारी इन छुट्टियों को अर्हक सेवा के लिए अनुमत करें अगर किसी कर्मचारी की छुट्टियां मंजूर की जाएं।

1. सिविल दंगे के कारण वह तैनाती पर आने में अथवा पुनः तैनात प- आने में असमर्थ हो।

2. उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के कारण।

15. पेंशन के लिए निलम्बन अवधि की गणना :—ऐसे मामलों में कोई कर्मचारी निलम्बन पर रहा तथा जांच से से वह दोषमुक्त पाया गया तो उसके द्वारा बितायी गई उक्त पेंशन के अर्हक सेवा की अवधि गिनी जाएगी तथा अन्य मामलों में निलम्बन की अवधि की तब तक गणना नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामले जो इन नियमों के तहत आते हैं उनका सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश न करे कि उक्त अवधि की गणना अर्हक सेवा में की जाएगी।

16. बरखास्तगी एवं निष्कासन पर सेवा का समपहरण कर्मचारी के बरखास्तगी अथवा निष्कासन के मामलों में उसकी द्वारा की गई पिछली सेवाएं पेंशन के प्रयोजन समाप्त मानी जाएगी।

17. सेवा से त्यागपत्र के समय सेवा समपहरण :—सेवा या पद से त्यागपत्र देने से पिछली सेवाएं समाप्त हो जायेंगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे सार्वजनिक हित में वापस न लिया हो। ऐसे मामलों केवल अध्याय 9 के तहत उपदान की अदायगी की जाएगी। ये अदायगी उन कर्मचारियों को की जाएगी जिनके लिए कि उपदान अधिनियम 1972 तथा उसके तहत बनाये गये नियम लागू होते हैं।

18. पुनः बहाली पर पिछली सेवा की गणना :—1. अगर किसी कर्मचारी को बरखास्त, या निष्कासित किया जाता है या अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाता है किन्तु अपील या पुनरीक्षा पर पुनः बहाल किया जाता है तो वह अपनी पिछली सेवाओं को अर्हक सेवा की गणना कराने का हकदार है।

2. वर्खास्तिगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, यथा स्थिति तथा पुनः बहाली तथा निलम्बन की अवधि यदि कोई हो के मध्य सेवा में अवरोध की अवधि अर्हक सेवा के लिए नहीं गिनी जा सकती जब तक कि तैनाती अथवा बहाली करनेवाले प्राधिकारी के द्वारा विशेष आदेश द्वारा छुट्टी को नियमित नहीं कर दिया जाता।

19. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्धन :—नियुक्त किए गये पद पर कोई भी कर्मचारी निवर्तन पेंशन के लिए (किन्तु अन्य श्रेणी के पेंशन के लिए नहीं) अपनी अर्हक सेवा परिवर्धन कराने का हकदार होगा परन्तु यह अवधि उसकी सेवा की अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी या वह वास्तविक अवधि जिसमें कि उसकी भर्ती के बाद उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक न हो जाती है अथवा 5 वर्ष की अवधि जो भी स्पूनतम हो बशर्ते कि उसकी नियुक्ति का पद निम्न में से कोई हो :—

1. सामान्यतया जिस पद के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी नियुक्त किए जाते हैं।

2. जिन पदों के लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशिष्ट योग्यताएं या विज्ञान एवं तकनीकी अथवा व्यवसाय में अनुभव अनिवार्य है।

परन्तु यह रियायत उन कर्मचारियों के लिए ग्राह्य नहीं होगी जिनकी सेवा छोड़ते समय अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम न हो।

टिप्पणी :—प्रशासन उक्त पदों की नियुक्ति की रीति के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विनिर्धारित व्यावसायिक अनुभव अथवा उम्र के अनुसार ऐसे पदों की पहचान करेगा।

20. सेवा में अवरोध का प्रभाव :—निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में कर्मचारी की पिछली सेवा समाप्त मानी जाएगी।

1. प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी

2. प्राधिकृत छुट्टी की अनुपस्थिति के साथ अनधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थिति कर्मचारी के पद को मूल रूप से न भर लिया जाए।

3. निलम्बन जहां पर कि बहाली के तुरंत बाद हुआ हो चाहे वह उसी पद पर या अन्य पद पर अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है अथवा उसे सेवा निवृत्ति की अनुमति दी जाती है अथवा निलम्बन के समय अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी करके सेवा निवृत्त हो जाता है।

4. गैर अर्हक सेवा पर हस्तांतरण

21. बिना छुट्टियों के अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण छुट्टियों में परिवर्धन—नियुक्त प्राधिकारी पश्चात दर्शाई अनुपस्थिति की अवधि को बिना भत्ते सहित छुट्टियों में परिवर्तित कर सकता है।

22. सेवा में अवरोध की शर्तें :—1. नियुक्त प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी की सेवा के अवरोध को आदेश द्वारा माफ कर सकता है।

(क) बशर्ते कि यह अवरोध कर्मचारी के नियंत्रण में बाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ हो।

(ख) एक या एक से अधिक अवरोध की अवधि की कुल सेवा यदि कोई हो 5 वर्ष से अधिक न हो।

(ग) दो या एक से अधिक अवरोध यदि कोई हों तो एक वर्ष से अधिक न हों।

2. इस विनियम के तहत माफ की गई अवधि के अवरोध को अर्हक सेवा में नहीं माना जाएगा।

अध्याय 5—परिलब्धियां एवं औसत परिलब्धियां

23. परिलब्धियां 1. वर्ग 1 व 2 कर्मचारियों के मामले में परिलब्धियों से तात्पर्य मूलभूत नियमावली 9(21) में विनिर्धारित वेतन तथा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते से है जिसे कि वर्ग 1 या 2 के अधिकारी उनके/उसकी सेवा निवृत्ति अथवा उनके/उसकी मृत्यु के दिन पा रहे थे।

2. वर्ग 3 या 4 के कर्मचारियों के मामले में परिलब्धियों से तात्पर्य निम्नलिखित में से कोई भी जिसे कि वह सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु की तिथि से तुरंत पहले पा रहे/रही थी तथा जैसा कि उसने विकल्प दिया हो :—

(क) मूलभूत नियमावली 1(21) के तहत विनिर्धारित वेतन जिसमें महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, उजरत दर उपार्जन, प्रोत्साहन भत्ता तथा ऐसी अन्य अदायगी जो उस योजना के तहत लागू हो, भुगतान किया जाए आदि शामिल हैं।

(ख) मूलभूत नियमावली 1(21) के तहत विनिर्धारित उजरत दर उपार्जन, प्रोत्साहन अदायगी और ऐसी अन्य अदायगी जो इस योजना के तहत जहां लागू हो भुगतान किया जाए आदि शामिल हैं।

टिप्पणी—1. वेतन समझौता दिनांक 4 फरवरी 1981 के वहत 1 जनवरी 1980 से वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों को दिया गया विशेष स्थाई भत्ता भी उपरोक्त (क) व (ख) के तहत वेतन में माना जाएगा।

2. कर्मचारी की सेवा निवृत्ति या उसके सेवा छोड़ने के एक महीने पूर्व परिलब्धियों के लिए उसे विकल्प देना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो लेख के समझौते-पूर्व उनके परिवार के सदस्य विकल्प दे सकते हैं।

3. अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है अथवा वह सेवा निवृत्ति से पूर्व अपनी तैनाती से ऐसी छुट्टियों पर अनुपस्थित है जिनमें कि वह झूटी वेतन का हकदार है अथवा

सेवा के बिना सम्पूरण के साथ निलम्बन से उसकी बहाली की गई है तो उस अवधि में वह तैनाती से पहले अनुपस्थित होता या निलम्बित न होता तो उसके द्वारा गृहीत परिलब्धियाँ उक्त उद्देश्य के लिए परिलब्धियाँ मानी जाएंगी।

परन्तु वेतन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी चाहे वह वेतन वृद्धि के कारण हो अथवा अन्यथा तथा जो सेवा निवृत्त पूर्व अर्जित छुट्टियों के प्रथम 120 में नहीं हुई है, परिलब्धियों के तहत नहीं आएगी।

4. उच्च पद पर जाने के बाद चाहे स्थानापन्न होगा, अस्थाई हो अगर किसी कर्मचारी सेवा निवृत्ति से तुरंत पूर्व छुट्टी पर जाता है जिसके लिए वह छुट्टी वेतन का हकदार है तो ऐसी उच्च नियुक्ति में उसके द्वारा गृहीत परिलब्धियों का लाभ तभी दिया जाएगा जब कि यह प्रमाणित किया जाए कि कर्मचारी छुट्टी पर जाने तक उक्त उच्च पद को धारण किए रहता।

5. अगर किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है अथवा वह असाधारण छुट्टियों पर तैनाती से अनुपस्थित रहता है अथवा निलम्बित किया जाता है तथा उस अवधि को सेवा में नहीं गिना जाता तो उसके ऐसी छुट्टी पर जाने से तुरंत पूर्व अथवा निलम्बन के समय तक उसके द्वारा गृहीत परिलब्धियों की गिनती इस विनियम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

6. विदेश सेवा पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में ट्रस्ट में रह कर जो परिलब्धियाँ वे प्राप्त करते (अगर विदेश सेवा पर न जाते) केवल उक्त परिलब्धियाँ ही मानी जाएंगी।

7. ऐसे कर्मचारी जो उजरत दर/प्रोत्साहन/परिणामी योजना के तहत अदायगी की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए उपदान तथा परिवार पेंशन के तहत परिलब्धियों से तात्पर्य उन परिलब्धियों से है जैसी कि उप विनियम (2) अथवा विनियम 24 में विनिर्धारित औसत परिलब्धियों जो कि कर्मचारी के लिए लाभदायक हों।

8. मूल पद पर नियुक्ति वाले कर्मचारियों के मामले में जो अन्य नियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करते हैं अथवा अस्थाई नियुक्ति पर कार्य करते हैं, तो उनके लिए परिलब्धियों से तात्पर्य :—

(क) वह नियुक्ति जिसमें कि उसने स्थानापन्न के रूप में अथवा अस्थाई नियुक्ति के रूप में कार्य किया हो तो उस समय गृहीत परिलब्धियों की गणना इस विनियम के तहत की जाएगी/अथवा

(ख) अगर वह अपने मूल पद पर रहा हो तो उस समय उसके द्वारा गृहीत परिलब्धियाँ जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हों, की गणना की जाएगी।

24. (1) औसत परिलब्धियों से तात्पर्य कर्मचारी सेवा छोड़ने के तुरंत पूर्व या उसकी मृत्यु से पूर्व उसके द्वारा 10 महीने में गृहीत औसत परिलब्धियों से होगा।

(2) अन्तिम 10 महीने की सेवा के समय अगर कोई कर्मचारी तैनाती से ऐसी छुट्टियों पर अनुपस्थित है जिनके लिए कि वह छुट्टी वेतन का हकदार है या निलम्बन के बाद बिना सेवा समाप्त

हुए उसकी बहाली की जाती है तो अगर उक्त अवधि में वह अनुपस्थित न होता या निलम्बित न होता तो उसमें उसके द्वारा गृहीत परिलब्धियों की गणना विनियम 23 के प्रावधानों के अन्वीन की जाएगी।

अगर कोई कर्मचारी अन्तिम 10 महीने के दौरान तैनाती से असाधारण छुट्टियों पर अनुपस्थित रहता है अथवा निलम्बित रहता है जिसमें उसकी सेवा की गणना नहीं की जाती है तो औसत परिलब्धियों की गणना से उपरोक्त छुट्टी की अवधि अथवा निलम्बन की अवधि निकाल दी जाएगी तथा 10 महीने से पूर्व की समान अवधि इसमें मिला ली जाएगी।

टिप्पणी—ऐसी श्रेणी जो उजरत दर/परिणामी अदायगी प्रोत्साहन योजना के तहत आती है उनके मामले में कर्मचारी के सेवा छोड़ने के 10 महीने पूर्व अथवा मृत्यु के पूर्व कर्मचारी लगाता है छुट्टियों पर या तो उपरोक्त बताए गए के अनुसार परिलब्धियों के औसत की गणना की जाएगी बशर्ते कि उजरत दर/परिणामी अदायगी/प्रोत्साहन उपार्जन का औसत वही माना जाएगा जैसा कि वह लगानार छुट्टी प्रारम्भ होने की तारीख से तुरंत बाद पूरे 10 महीने के दौरान परिलब्धियों का औसत अर्जन करता।

25. जो कर्मचारी उपदान अधिनियम 1972 के तहत आते हैं उनके लिए विनियम 23 व 24 की परिलब्धियों/औसत परिलब्धियों, उपदान भुगतान के लिए लागू नहीं होगी जिनके मामले में इन विनियमों के अध्याय 9 में उल्लिखित विनियम 45 लागू होगा।

अध्याय 6—पेंशन की राशि

26. ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिनकी अर्हक सेवा 10 वर्षों से कम नहीं है, इन विनियमों के तहत सेवा निवृत्त से रहे हैं तो पेंशन की रकम नीचे निर्धारित किए गए के अनुसार होगी, अर्थात् :—

छः मास की अवधि से पूर्ण की गई अर्हक सेवा	पेंशन का मानदण्ड	(प्रति वर्ष अधिकतम पेंशन रु० में) वर्ग 1 व 2 के अधिकारी एवं वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए 5 के विनियम 23(4) की परिलब्धियों का विकल्प दिया है	(प्रति वर्ष अधिकतम पेंशन रु० में) वर्ग 3 व 4 के उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने अध्याय 5 के विनियम 23 1-क की परिलब्धि का विकल्प दिया है
(1)	(2)	(3)	(4)
		रु० पैसे	रु० पैसे
20	औसत परिलब्धियों का 10/80	3750.50	2700.00
21	10 1/2 / 80	3937.50	2835.00

(1)	(2)	(3)	(4)
22	11/80	4125.50	2970.00
23	11½/80	4500.00	3105.00
24	12/80	4687.50	3240.00
25	12½/80	4875.00	3375.00
26	13/80	5062.50	3510.00
27	13½/80	5250.00	3645.00
28	14/80	5437.50	3780.00
29	14½/80	5625.00	3915.00
30	15/80	5812.50	4050.00
31	15½/80	6000.00	4185.00
32	16/80	6187.50	4320.00
33	16½/80	6375.00	4455.00
34	17/80	6562.00	4590.00
35	17½/80	6750.00	4725.00
36	18/80	6937.00	4860.00
37	18½/80	7125.00	4995.00
38	19/80	7312.00	5130.00
39	19½/80	7500.00	5265.00
40	20/80	7687.50	5400.00
41	20½/80	7875.00	5535.00
42	21/80	8062.50	5670.00
43	21½/80	8250.00	5805.00
44	22/80	8437.50	5940.00
45	22½/80	8625.00	6075.00
46	23/80	8812.50	6210.00
47	23½/80	9000.00	6345.00
48	24/80	9187.50	6480.00
49	24½/80	9375.00	6615.00
50	25/80	9562.50	6750.00
51	25½/80	9750.00	6885.00
52	26/80	9937.50	7020.00
53	26½/80	10125.00	7155.00
54	27/80	10312.50	7290.00
55	27½/80	10500.00	7425.00
56	28/80	10687.50	7560.00
57	28½/80	10875.00	7695.00
58	29/80	11062.50	7830.00
59	29½/80	11250.00	7965.00
60	30/80	11437.50	8100.00
61	30½/80	11625.00	
62	31/80	11812.50	
63	31½/80	12000.00	
64	32/80	12000.00	
65	32½/80	12000.00	
66	33/80		

टिप्पणी—1. उपरोक्त में किसी भी बात के उल्लेख के होते हुए भी और अवधि पेंशन की रकम अध्याय X के विनियम 47 (1) के तहत ग्राह्य परिवार पेंशन से कम नहीं होगी।

2. सेवा की अवधि की गणना करते समय 6 माह के समकक्ष वर्ष या उससे अधिक की मिलन को 6 महीने की पूरी अवधि मानी जाएगी।

3. पेंशन का निर्धारण मासिक दर से किया जाएगा तथा पूर्ण रूपों में होगा और जहां पेंशन रूपों की भिन्न में आती हो तो रोज उच्चतम रूपों में पूर्णक बना दिया जाएगा।

4. किसी भी मामले में उस विनियम के तहत निर्धारित अधिकतम पेंशन से अधिक पेंशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. पेंशन की रकम न्यूनतम रु० 40/- प्रति माह होगी।

6. ऐसे मामलों में जहां पेंशन वृद्धि हो जाती है (तदर्थ वृद्धि को शामिल करके) और अगर वह रु० 40/- प्रति माह से है, यदि कोई हो तो अंतराल को पेंशन में वृद्धि करके पूरा कर दिया जाएगा।

27. वर्ग 1 व 2 अधिकारी तथा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जिन्होंने अध्याय 5 में विनियम 23(11)(ख) के तहत परिलब्धियों का विकल्प दिया है तथा जो 31 मार्च 1979 को सेवा में थे तथा उस दिनांक को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो रहे हैं जब तक कि निम्नलिखित मानदण्ड से उनकी पेंशन तय की जाती—

1. पेंशन के लिए गणना की जाने वाली प्रथम औसत परिलब्धियां रु० 1000/- तक औसत परिलब्धियों की 50%
2. पेंशन के लिए गणना की जाने वाली अगली औसत परिलब्धियां रु० 500/- तक औसत परिलब्धियों की 45%
3. पेंशन के लिए गणना की जाने वाली शेष औसत परिलब्धियां 40%, किन्तु निम्न टिप्पणी (2) की सीमा के तहत।

टिप्पणी—1. उपरोक्त स्लैब के आधार पर गणना की गई पेंशन अधिकतम अर्हक सेवा 33 वर्ष से संबंधित होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति के समय अर्हक सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 33 वर्ष से कम है तो उनकी पेंशन के अनुपात की रकम उस आधार पर होगी जो कि उन्हें 33 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद अधिकतम पेंशन ग्राह्य होती।

2. अध्याय 7 के विनियम 32(3) और 32(4) के तहत उपरोक्त स्लैब के अनुसार निर्धारित पेंशन तथा अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता कीमत सूचकांक 328 तक ग्राह्य राहत राशि प्रति माह रु० 1500/- से अधिक नहीं होगी। अगर पेंशन की राशि स्वयं रु० 1500/- प्रति माह से अधिक हो जाती है, तो सम्पूर्ण 33 वर्ष की सेवा के लिए अधिकतम पेंशन की राशि रु० 1500/- प्रति माह तक सीमित कर दी जाएगी तथा सूचकांक 328 तक किसी भी राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

20. सेवा उपदान—ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जो इन नियमों के अनुसार सेवा निवृत्त हो रहे हैं तथा उन्होंने 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की है तो पेंशन के बढने सेवा उपदान की देय रकम निम्नलिखित प्रकार से होगी, अर्थात् :—

अर्हक सेवा के
लिए 6 माह
की अवधि पूर्ण
करने पर

सेवा उपदान
का मानक

(1) (2)

1	परिवर्धियों का $\frac{1}{2}$ माह
2	" 1 माह
3	" $1\frac{1}{2}$ माह
4	" 2 माह
5	" $2\frac{1}{2}$ माह
6	" 3 माह
7	" $3\frac{1}{2}$ माह
8	" 4 माह
9	" $4\frac{1}{2}$ माह
10	" $4\frac{1}{2}$ माह
11	" $5\frac{1}{2}$ माह
12	" $5\frac{1}{2}$ माह
13	" $5\frac{1}{2}$ माह
14	" $6\frac{1}{2}$ माह
15	" $6\frac{1}{2}$ माह
16	" 7 माह
17	" $7\frac{1}{2}$ माह
18	" $7\frac{1}{2}$ माह
19	" $8\frac{1}{4}$ माह

सेवा की अवधि की गणना करते समय 6 माह के बराबर और उससे अधिक वर्ष की भिन्न 6 माह की सम्पूर्ण अवधि मानी जाएगी।

अध्याय 7—पेंशन/परिवार पेंशन पर राहत

29. पेंशन दर तदर्थ राहत—वर्ग 1 और 2 के अधिकारी जो 1 जनवरी 1973 से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए और वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1969 को सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वे 1 सितम्बर, 1969 (अर्थात् सितम्बर 1969 माह की पेंशन जो अक्टूबर, 1969 में देय होगी) से निम्नलिखित प्रकार से तदर्थ तहत के पात्र होंगे।

पेंशन की राशि	पेंशन में तदर्थ वृद्धि की दर
(1)	(2)
रु० 30/- तक पेंशन	रु० 15/- प्रति माह
रु० 30/- से अधिक तथा रु० 75/- से कम पेंशन।	रु० 17.50 प्रति माह

(1)

(2)

रु० 75/- से अधिक तथा रु० 200/- से कम पेंशन। रु० 20/- प्रति माह

रु० 200/- से अधिक पेंशन ऐसी तदर्थ वृद्धि जिससे पेंशन कुल रु० 220/- तक हो।

30. पेंशन पर अतिरिक्त तदर्थ राहत—वर्ग 1 और 2 के अधिकारी जो 1 जनवरी 1973 से पहले सेवा निवृत्त हो गए हैं और वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी 1969 से पहले सेवा निवृत्त हो गए हैं तो वे 1 जनवरी 1973 (अर्थात् जनवरी 1973 की पेंशन जो फरवरी 1973 में देय होगी) से उपरोक्त विनियम 29 के तहत ग्राह्य तदर्थ राहत के अलावा अतिरिक्त तदर्थ राहत के पात्र होंगे।

पेंशन (मूल पेंशन पर आधारित) पेंशन पर तदर्थ राहत की राशि

रु० 85/- से कम	रु० 15/- प्रति माह
रु० 85/- से अधिक और रु० 210/- से कम	रु० 21/- प्रति माह
रु० 210/- तथा उससे अधिक एवं रु० 500/- से कम	रु० 25/- प्रति माह
रु० 500/- और अधिक	रु० 35/- प्रति माह

टिप्पणी—अतिरिक्त तदर्थ राहत की गणना करने के प्रयो-जनार्थ अनुकम्पा भत्तों को मिला कर मूल पेंशन में उक्त विनियम 21 में उल्लिखित तदर्थ वृद्धि शामिल नहीं है, परन्तु पेंशन का लघुकृत हिस्सा, यदि कोई हो, शामिल है।

31. वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी 1969 से 31 दिसम्बर 1973 के बीच सेवा निवृत्त हुए हैं वे भी 1 जनवरी 1979 से उपरोक्त विनियम 30 में निर्धारित दरों के अनुसार तदर्थ राहत के पात्र होंगे।

32. पेंशन पर आर्वाधिक राहत—अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता कीमत सूचकांक (1960-100) के विचलन के आधार पर पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को आवधिक राहत निम्नलिखित विनिर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुसार प्रदान की जायेगी:—

1. वर्ग 1 व 2 के अधिकारी जो 1 जनवरी, 1974 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो जनवरी, 1969 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं उन्हें अखिल भारतीय कामगार उपभोक्ता कीमत सूचकांक के 200 (1960-100) पाइण्ड्स के ऊपर 12 माह के औसत के अनुसार हर एक 16 पाइण्ड्स की वृद्धि होने पर प्रत्येक अवसर पर मूल पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से आवधिक राहत दी जायेगी बशर्ते कि राहत की

की कम से कम राशि रु. 5/- तथा अधिकतम राशि रु. 25—प्रतिमाह होगी। 1 जनवरी, 1973 के आधार पर होगी।

2. आवधिक राहत की मात्रा का परिकलन निम्न-लिखित आधार पर गणना करके किया जायेगा :—

(क) मूल पेंशन जैसा कि विनियम 30 के तहत टिप्पणी में बतायी गयी है।

(ख) तदर्थ राहत जहाँ कि विनियम 29 के तहत ग्राह्य है।

(ग) विनियम 30 के तहत ग्राह्य अतिरिक्त तदर्थ राहत।

3. वर्ग 1 व 2 के अधिकारी जो 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अखिल भारतीय कामगार उपभोक्ता कीमत सूचकांक 250 (1960=100) पाइण्ड्स के ऊपर 12 माह के औसत के अनुसार हरेक 20 पाइण्ड्स की वृद्धि होने पर प्रत्येक अवसर पर मूल पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से आवधिक राहत दी जाएगी बशर्ते कि राहत की कम से कम राशि रु. 5—तथा अधिकतम राशि रु. 25 प्रति माह होगी। यह 1 जनवरी, 1974 के आधार पर होगी परन्तु यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक के उस पाइण्ड्स तक सीमित कर दी जायगी जहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार के पेंशन पाते कर्मचारियों को सीमित है।

वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1978 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा जिन्होंने अध्याय 5 के विनियम 23(2)(ख) के तहत परिलब्धियों का विकल्प दिया है तो उन्हें 1 जनवरी, 1979 से इस विनियम के उपविनियम 3 में वर्ग 1 तथा 2 के अधिकारियों को ग्राह्य आवधिक राहत के अनुसार आवधिक राहत दी जायगी।

5. वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1974 31 दिसम्बर, 1978 के बीच सेवा निवृत्त हो जाते हैं तथा जो 1 जनवरी, 1979 से अध्याय 5 के विनियम 23(2)(क) के तहत वेतन से अनिवार्य रूप से नियमित होते हैं तो उन्हें अखिल भारतीय कामगार उपभोक्ता कीमत सूचकांक (1960=100) के अधिक पाइण्ड्स के ऊपर 12 माह के औसत के अनुसार हरेक 20 पाइण्ड्स की वृद्धि होने पर प्रत्येक अवसर पर मूल पेंशन का 4 प्रतिशत आवधिक राहत दी जायगी परन्तु यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक के उस पाइण्ड्स तक सीमित कर जायगी जहाँ तक समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के पेंशनर्स को अनुमत है बशर्ते कि प्रत्येक अवसर पर यह रकम न्यूनतम रु. 5/- तथा अधिकतम रु. 52—होगी। यह राहत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के समय उक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर उसके द्वारा गृहीत परि-

वर्तनीय महंगाई भत्तों पर आधारित होगी।

6. वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी जो अध्याय 5 के विनियम 23(2) (क) में निर्धारित वेतन का विकल्प देते हैं और जो 1 जनवरी, 1979 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त होते हैं तो उन्हें इस विनियम के उप विनियम 5 में निर्धारित शर्तों एवं दर के अनुसार आवधिक राहत प्रदान की जायगी।

टिप्पणी :—1. इस विनियम में आवधिक राहत के प्रयोजनार्थ पेंशन से तात्पर्य मंजूर किए गये अनुकम्पा भत्ते या पेंशन जिसमें लघुतम पेंशन का भाग भी शामिल है, यदि कोई हो, से है।

2. रुपये की भिन्न नजदीकी 10 पैसे में तथा 5 पैसे की भिन्न अगले 10 पैसे में पूर्ण कर दी जायगी।

3. उपरिखचित राहत प्रदान करना ऐसे संशोधनों के के तहत होगी जैसे कि भारत सरकार समय-समय पर सूत्र और तरीका तैयार करे।

33. पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के किसी भी संगठन जैसे केन्द्रीय या राज्य सरकार/कम्पनी/संगठन/उपक्रम या स्वायत्त निकाय या राष्ट्रीयकृत बैंक या स्थानीय निधि आदि में नियोजित या पुनर्नियोजित होने की स्थिति में तदर्थ राहत, अतिरिक्त तदर्थ राहत और आवधिक राहत की अवायगी बन्द कर दी जायगी।

34. परिवार पेंशन पर राहत :— 1. परिवार पेंशन पर तदर्थ राहत :— वर्ग 1 व 2 के अधिकारी जो 1 जनवरी, 1973 से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तथा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1969 से पहले सेवा निवृत्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 अक्टूबर, 1975 से विनियम 30 में निर्धारित दरों के अनुसार तदर्थ राहत प्रदान की जायगी।

2. परिवार पेंशन पर आवधिक राहत :— (क) वर्ग 1 व 2 के अधिकारियों जो 1 जनवरी, 1974 से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1969 से पहले सेवा निवृत्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 अक्टूबर, 1975 से विनियम 32(1) व 32(2) में निर्धारित दरों के अनुसार आवधिक राहत की अनुमति दी जायगी।

(ख) वर्ग 1 व 2 के अधिकारी जो 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं या, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 अक्टूबर, 1975 से विनियम 32 के तहत निर्धारित दरों पर आवधिक राहत प्रदान करने की अनुमति दी जायगी।

(ग). वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी 1979 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो जिन्होंने विनियम 23(2) के तहत बतन का विकल्प दिया हो तो उनके परिवार को जनवरी 1979 से विनियम 32(3) की दरों के तहत आवधिक राहत प्रदान की जायगी।

(घ) वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी 1974 तथा 31 दिसम्बर 1978 के बीच सेवा निवृत्त हो जाते हैं या उनकी इस दौरान मृत्यु हो जाती है और जो विनियम 23(2) (क) के तहत बतन के लिए अनिवार्य रूप से नियमित होते हैं तो उनके परिवार को 1 जनवरी 1979 से विनियम 32(5) के तहत दरों पर आवधिक राहत प्रदान की जायगी।

(ङ) वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी जो 1 जनवरी 1979 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तथा विनियम 23(2) (क) में निर्धारित बतन का विकल्प देते हैं तो 1 जनवरी 1979 से उनके परिवार को विनियम 32(5) की दरों के अनुसार आवधिक राहत प्रदान की जायगी।

अध्याय—7 पेंशन का लघुकरण

35(1) कोई भी कर्मचारी पेंशन की एकमुश्त अदायगी के लघुकरण के इसके बाद विनिर्धारित शर्तों के अधीन पेंशन को लघुकृत कराने का हकदार होगा। परन्तु इस प्रकार लघुकृत की गई पेंशन या इन विनियमों की तालिका में निर्धारित पेंशन की 1/3 से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी:—इन विनियमों के तहत प्रदान किए गये अनुकम्पा भत्ते पेंशन के लघुकरण के प्रयोजनार्थ पेंशन माने जायेंगे।

2. अवैध पेंशनर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के पेंशनर उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर निवृत्त/सेवानिवृत्ति के समय उन्हें मंजूर की गई पेंशन का 1/3 भाग चिकित्सा जांच कराये बिना लघुकृत करा सकते हैं तथा लघुकरण पूर्ण माना जायगा अर्थात् सेवा निवृत्त कर्मचारी अपनी लघुकृत पेंशन पाने का हकदार उस तिथि से हो जायगा जिसको उसका आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाता है।

3. ऐसी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में जो सेवानिवृत्त होने की दिनांक के एक वर्ष बाद लघुकृत पेंशन के लिए आवेदन करते हैं तथा अवैध पेंशनर के मामले में लघुकृत पेंशन केवल चिकित्सा जांच की शर्तों के अधीन देय होगी तो उक्त दोनों मामलों में लघुकृत पेंशन की अदायगी के लिए निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायगी:—

पेंशन के लघुकरण कराने का आवेदन प्राप्त हो जाने पर मंजूर प्राधिकारी आवेदक के पास लघुकरण के लिए एक मुश्त अदायगी का लेखा अधिकारी का प्रमाण पत्र भेजेंगे इस शर्त पर कि उसे ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी के

पास रिपोर्ट करनी होगी जैसा कि मंजूर प्राधिकारी लघुकरण के विषय को उपयुक्त समझे तथा उसी समय उसे निर्देश भेजेंगे कि वह उस आदेश के तीन महीने के अन्दर उक्त चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो अथवा अगर उसने उस तारीख के तीन महीने के अन्दर अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख में पहले ही लघुकरण के लिए आवेदन किया है परन्तु किसी भी मामले में सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख से पहले नहीं। इस सूचना में लघुकरण की प्रशासनिक मंजूरी होगी परन्तु मंजूरी आदेश में निर्धारित अवधि में अगर चिकित्सा जांच नहीं होती तो यह मंजूरी समाप्त हो जायगी। अगर आवेदक विनिर्धारित समय में उपरोक्त कथित चिकित्सा प्राधिकारी के पास चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित नहीं होता तो मंजूरी प्राधिकारी अपने स्वविवेक से पेंशन के लघुकरण के लिए आवेदन से नया आवेदन लिए बिना तीन महीने की और अवधि के लिए प्रशासनिक मंजूरी का नवीकरण कर सकता है। चिकित्सा जांच होने से पहले आवेदन किसी भी समय लिखित नोटिस भेजकर अपने आवेदन को वापस ले सकता है परन्तु उसके द्वारा चिकित्सा प्राधिकारी के पास प्रस्तुत होने पर यह विकल्प समाप्त हो जाएगा।

परन्तु यदि चिकित्सा प्राधिकारी यह निवेश देता है कि लघुकरण के प्रयोजनार्थ उसकी उम्र वास्तविक उम्र से अधिक मानी जायगी तो आवेदक इसी सूचना मिलने पर दो सप्ताह के अन्दर लिखित नोटिस भेजकर अपना आवेदन वापस ले सकता है परन्तु अगर यह रकम मंजूरी आदेश में पहले ही दर्शाई गयी हो तो चिकित्सा प्राधिकारी के परिणाम की सूचना प्राप्त होने की दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर अपना आवेदन वापस ले सकता है।

टिप्पणी 1. उपरोक्त निर्धारित दो सप्ताह की अवधि के अन्दर अगर आवेदक अपना आवेदन वापस नहीं लेता तो यह समझा जायगा रकम का प्रस्ताव उसे स्वीकार्य है।

2. इस विनियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन लघुकरण प्रारम्भ हो जायगा तथा पेंशन का लघुकृत भाग प्राप्त करने वाला शीर्षक समाप्त हो जायगा तथा पेंशन का लघुकृत भाग प्राप्त करने का शीर्षक उस दिनांक को प्रोद्भूत होगा। जिसको कि चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। लघुकृत पेंशन की अदायगी यथा शीघ्र की जायगी परन्तु विरुद्ध जीवन के मामले में तब तक कोई अदायगी नहीं की जायगी जब तक कि लघुकरण की लिखित स्वीकृति प्राप्त न हो गई हो अथवा लघुकरण के लिए किए गये आवेदन की वापस लेने की अवधि समाप्त न हो गयी हो। वास्तविक अदायगी की कोई तारीख हो परन्तु भुगतान की गई रकम और पेंशन का प्रभावी होना दोनों एक ही होंगे मानो कि लघुकृत रकम की अदायगी उस तारीख को कि गई है जिसको कि लघुकरण प्रारम्भ होता है। अगर पेंशन का लघुकृत

भाग लघुकरण के सम्पूर्ण होने की दिनांक के बाद, गृहीत किया जा चुका है तो गृहीत रकम लघुकरण में देय रकम में से घटा दी जायगी।

3. चिकित्सा जांच के सम्बन्ध में आवेदन को लिखित या मौखिक पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में अगर उसके द्वारा दिए गये विवरण में उसकी जानकारी स्वयं कोई जानकारी गलत होती है या जानबूझ कर किसी तथ्य को दबाता है तो वास्तविक अदायगी किए जाने से पहले मंजूरी अधिकारी मंजूरी रद्द कर सकता है तथा ऐसा विवरण अथवा तथ्यों को दबाने की कार्रवाई गम्भीर दुराचार मानी जायगी।

4. अगर किसी पेंशनर को चिकित्सा आधार पर लघुकरण मना कर दिया जाता है अथवा वह अपनी वास्तविक उम्र में कुछ वर्षों को जोड़ने के कारण लघुकरण स्वीकार करने से मना कर देता है तो वह दूसरी बार अपने खर्च पर चिकित्सा जांच के लिए आवेदन कर सकता है बाढ़े भले ही प्रथम उक्त प्रक्रिया से एक वर्ष बीत गया हो और ऐसी पुनः जांच चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से की जायगी।

5 लघुकरण पर देय एकमुश्त गणना—लघुकरण पर एकमुश्त अदायगी की गणना सारणी अथवा मौजूदा मूल्य की सारणी के अनुसार की जायगी जिसकी समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अपने सिविल सेवा विनियम में निर्धारण किया जायगा। मौजूदा मूल्य की तालिका इस विनियम की सारणी में दी गई है। आवेदक को लागू होने वाली तालिका अगर लघुकरण के लिए प्रशासनिक मंजूरी की दिनांक और वह दिनांक जिसको कि लघुकरण देय सम्पूर्ण होता है उनके बीच संशोधित हो जाती है तो वह अदायगी संशोधित तालिका के अनुसार की जायगी परन्तु अगर संशोधित तालिका पिछली

प्रचलित तालिका से उसक लिए कम लाभदायक है तो आवेदक के लिए यह छूट होगी कि संशोधन की सूचना प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अन्दर वह लिखित रूप से नोटिस भेजकर अपने आवेदन को वापस ले सकता है।

37. पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर लघुकरण की अदायगी अगर लघुकरण प्रारम्भ होने या उसके पश्चात लघुकरण मूल्य की अदायगी प्राप्त किए बिना पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो यह रकम उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जायगा।

38. पेंशन के लघुकरण को मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्न होंगे :—

1. वर्ग 1 के अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष
2. वर्ग 2 के अधिकारियों के मामले में उपाध्यक्ष
3. वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी।

39. आवेदन प्रपत्र चिकित्सा जांच एवं लघुकृत मूल्य की अदायगी आदि की प्रक्रिया होगी जैसी कि अध्यक्ष समय 2 पर निर्धारित करेंगे।

टिप्पणी 1. अध्याय 12 में इन विनियमों के तहत अगर पेंशन घटा दी गई है तो पेंशन का लघुकरण केवल घटी हुई पेंशन पर ही ग्राह्य होगी बशर्ते कि पेंशन में कमी स्थायी हों।

2. लघुकरण पेंशन के कारण पेंशन की रकम में घटोतरी पेंशनर द्वारा पेंशन के लघुकरण लघुकृत मूल्य के प्राप्त होने की दिनांक से प्रभावी होगी अथवा पेंशनर को इस बात के लिए प्राधिकृत करते हुए कि वह पेंशन के लघुकृत मूल्य को प्राप्त करने इस सूचना के तीन महीने के बाद जो भी जल्दी हो, प्रभावी होगी।

लघुकरण तालिका

(विनियम 35 को देखें)

पेंशन की लघुकरण मूल्य रु. 1 प्रति माह

अगले जन्म दिवस के समय आयु	खरीदी वर्ष की संख्या के अनुसार बतायी गई लघु-करण मूल्य	अगले जन्म दिवस के समय आयु	खरीदी वर्षों की संख्या के अनुसार बतायी गई लघु-करण मूल्य	अगले जन्म दिवस के समय आयु	खरीदी वर्षों की संख्या के अनुसार बतायी गई लघु-करण मूल्य
1	2	3	4	5	6
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.63
23	18.80	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	15.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30

1	2	3	4	5	6
27	18.21	50	13.25	73	6.01
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	52	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.40	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.78	82	3.72
37	16.52	59	10.46	83	3.52
38	16.31	61	9.81	84	3.32
39	16.09	62	8.48	85	3.13

टिप्पणी :—यह तालिका 4.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की दर के आधार पर है।

अध्याय X

उपदान

वर्ग 1 व 2 अधिकारी तथा वर्ग 3 व 4 कर्मचारी को उपदान भुगतान जो उपदान भुगतान अधिनियम 1972 द्वारा शासित नहीं है। मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान (1) कोई कर्मचारी जिसे "उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता और जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा समाप्त हो और वह सेवा के लिए पात्र हो जाता है तो विनियम 20 के तहत उपदान या विनियम 26 या 27 के तहत पेंशन को उसके निवृत्त होने पर मृत्यु एवं निवृत्त उपदान का भुगतान किया जायगा जो प्रति छः महीनों की अवधि अर्हक सेवाओं की समाप्ति में उसकी परिलब्धियों में एक चौथाई होगी। ये बातें अधिकतम निम्न शर्तों पर होगी :—

अ. विनियम 23 (1) (अ) के तहत जो कर्मचारी परिलब्धियों की परिभाषा के लिए विकल्प देते हैं उस प्रकार के वर्ग 3 एवं 4 कर्मचारियों को 15 गुना परिलब्धियां दी जाएगी।

आ. सभी अन्यो के मामलों में 16-1/2 गुना की परिलब्धियां दी जाएगी।

परन्तु जो कर्मचारी 3 जनवरी, 1981 के बाद निवृत्त हो रहे हैं और जो परिणाम योजना/पीस रेट योजना/प्रीमियम योजना भुगतान के तहत नियुक्त किया गया हो और उन्हें ऐसी जगहों में नियुक्त किया जाता है और ऐसी योजनाओं के तहत वे किसी को भुगतान के पात्र न हों और जहां कर्मचारी को चिकित्सा आयोग दुर्घटना आदि के कारण निम्न

वेतनमान लाया जाता है तो उपदान के लाभों को दो भागों में लघु किया जायगा जैसा कि—

(क) ऐसी वापसी तक के समय के लिए परिलब्धियों पर की उपदान को स्थिर करना या उस दिनांक की गयी सेवा के लिए समय दर कार्य का निर्णय करना चाहिए।

(ख) ऐसी वापसी के बाद की गयी सेवा के लिए कार्य से निकालते समय अतिरिक्त उपदान अंतिम परिलब्धियों के अनुसार होना चाहिए।

11. अगर किसी कर्मचारियों को, उपदान अधिनियम 1972 की भुगतान लागू न हों जो 5 वर्ष की सेवा की समाप्ति के उपरांत मर गया हो और मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान की राशि उसकी परिलब्धियों की 12 गुणा के बराबर हो या जो भी ज्यादा हों। (उपविनियम (1) के तहत) तो उसे अध्याय 11 में बताये गये अनुसार उसके परिवार को भुगतान करना होगा।

परन्तु इस विनियम के तहत देय मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान की राशि किसी भी हालत में निम्न प्रकार के अलावा नहीं बढ़ेगी :—

(प्र) विनियम 23 (11) (अ) के तहत परिलब्धियों की परिभाषा के अनुसार शासित होने के लिए जो वर्ग 3 व 4 के कर्मचारी अपनी इच्छा प्रकट करें उन्हें रु. 24,000 तक दी जायगी।

(प्रा) अन्य सभी मामलों में रु. 30,000 तक।

4. अन्य किसी कर्मचारी के लिए उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता और एक वर्ष की अर्हक सेवा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान की राशि उसकी मृत्यु के समय उसकी परिलब्धियों की दो गुना होगी।

अगर कोई कर्मचारी के लिए उपादान का भुगतान उपदान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता और एक वर्ष की अवधि सेवा के बाद और पांच वर्ष की अवधि सेवा समाप्त के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान के भुगतान की राशि उसकी मृत्यु के समय उसकी परिलब्धियों की छः गुना होगी।

5. अगर कोई कर्मचारी सेवा के समय मर जाय तो उपदान राशि को विनियम 50 के तहत प्रदत्त वही व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा या अगर ऐसा कोई न हो तो नीचे दिए प्रकार से भुगतान किया जाएगा :—

अ. अगर परिवार में एक या एक से अधिक सदस्य काम कर रहे हों जैसा कि विनियम 50 की मर्दे (1) (12) (3) और (4) में बताया गया है तो इसे ऐसे सभी सदस्यों को सम भाग में भुगतान किया जायगा। केवल विधवा पुत्री को छोड़ दिया जाएगा।

आ. अगर ऐसे सेवारत परिवार के सदस्य न हों जैसा कि ऊपर (अ) में बताया गया है, लेकिन एक या एक से अधिक परिवार के सदस्य जैसा कि विनियम 50 की मर्दे 5 में विधवा पुत्रियां कार्यरत हों और या एक से अधिक तक में है और सेवा कर रहे हैं तो ऐसे सभी सदस्यों को सम भाग उपादान का भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी :—11-7-76 में तीन माह की अवधि के उपरांत भी उपादान के भुगतान में विलंब हुआ हो तो उनके लिए पांच प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। उस महीने के अंत तक याने वास्तव में जिस महीने तक भुगतान किया जाता था दिया जायगा ब्याज तभी दिया जाएगा जब कि मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपादान की भुगतान देने में प्रशासनिक विलंब हुआ हो इसे स्पष्टीकृत करना होगा या संबंधित कर्मचारियों के नियंत्रण के बाहर के कारण हो। अन्य सभी मामलों में जहां ब्याज देना पड़ रहा है उस के लिए विलंब का दायित्व उसी पर रहेगा जो इसका दायित्व रखता हो और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

41. अवशिष्ट उपादान—अगर किसी कर्मचारी को उपदान अधिनियम 1972 की भुगतान लागू न हो और वह पेंशन या सेवा उपादान का पात्र बने और निवृत्ति दिनांक पांच वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाय, जिसमें अनिवार्य निवृत्ति भी दंड के रूप में शामिल तो ऐसे उपादान या पेंशन को मिलाकर उसकी मृत्यु के समय प्राप्त वास्तविक राशि, अगर उसमें तदर्थ वृद्धि हुई हो उसके साथ विनियम 40 के तहत मृत्यु एवं उपदान भी पात्र हो और उसके द्वारा लघुकृत पेंशन को किसी भाग भी लघुकृत मूल्य उसकी परिलब्धियों की बारह गुना की राशि से कम हों तो अवशिष्ट उपादान की कमी के समरूप में उसके परिवार को अध्याय 11 में बताये गये अनुसार मंजूरी की जा सकती है।

42. इस विनियम के तहत उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के पात्र हैं बशर्ते कि ये निम्न के लिए उच्चतम हो :—

(1) विनियम 23 (2) (अ) के तहत जो वर्ग 3 एवं (4) कर्मचारी परिलब्धियों के लिए विकल्प देते हैं उनके मामलों में रु. 1,800/—प्रतिशत।

(2) अन्य मामलों में रु. 2500 प्रतिमाह।

परन्तु किसी कर्मचारी की परिलब्धियों में अगर पिछले तीन वर्षों की सेवा के दौरान कम दर दिया गया हो जैसा कि विनियम 24 में दंड या औसतन परिलब्धियां बतायी गई हो तो प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर उपदान की मंजूरी के लिए इस परिलब्धियों के रूप में मानेगा।

43. मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान का तय होना : जब कोई कर्मचारी उपदान प्राप्त किए बगैर सेवा के समय या निवृत्ति के बाद मर जाता है तो :—

(1) बिना परिवार के, या

(2) किसी को नामित न किया हो, या

(3) उसके द्वारा नामित व्यक्ति नहीं ठिकता हो तो विनियम 40 के तहत देय मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान की राशि बोर्ड को तय की जायगी।

44 (1) अस्थायी कर्मचारियों को उपदान भुगतान :— एक अस्थायी कर्मचारी जिसे उपदान अधिनियम 1972 की भुगतान लागू नहीं होती और जो अधिवर्ष पर निवृत्त हो या कटौती के कारण सेवा से वर्षों की जाय या आगे की सेवा के लिए घोषित कर दें तो उसके लिए उसकी सेवा के प्रतिवर्ष समाप्ति के लिए परिलब्धियों में आधे दर से उपदान का पात्र बनेगा। परन्तु निवृत्ति के समय सेवा मुक्ति या आशंकता के समय पांच वर्ष से कम लगातार सेवा की समाप्ति नहीं होगी चाहिए।

परन्तु जो कर्मचारी 4 जनवरी, 1981 के बाद निवृत्त हो रहे हैं उनके मामलों में और जो परिणाम योजनाएं पीस रेट योजना/प्रिमियम योजना के तहत आने वाले पों पर काम किए गये हो और जहां ऐसी योजनाओं के तहत किसी भुगतान के पास न हों या जहां कामगार को निचले वेतनमान पर किसी चिकित्सा निर्धार्यता पर दुर्घटना आदि के कारण प्रत्यावर्तित कर दिया जाय तो उपादान को जैसा लाभ हों निम्न दो भागों में लघुकृत किया जाएगा।

(अ) उपदान ऐसे प्रत्यावर्तन या निर्धारित समय दर कार्यों पर देय परिलब्धियों पर स्थिर की जाती है ये उस दिनों तक की गयी सेवाओं के लिए होगी।

(आ) अवशिष्ट उपादान को ऐसे प्रत्यावर्तन या समय कार्य के निर्धारण के बाद की गयी सेवा के लिए रोजगार से हटाने समय देय अंतिम वेतन पर निर्धारित की जाती है। अस्थायी कर्मचारी के परिवार जिसको

उपदान अधिनियम 1972 का भुगतान लागू न हो और वह सेवा के समय मर जाता है तो उसके वेतन पर मृत्यु उपदान नीचे दी गयी शर्तों पर दी जाएगी।

(अ) एक वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद लेकिन तीन वर्ष की समाप्ति के पहले मृत्यु हो गयी हो तो उपदान के रूप में एक महीने की परिलब्धियों का भुगतान किया जाएगा।

(आ) तीन वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद लेकिन पांच वर्ष की समाप्ति के पहले मृत्यु हो गयी हो तो उपदान के रूप में दो महीनों की परिलब्धियों का भुगतान किया जायगा।

(इ.) पांच वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद लेकिन 10 वर्ष की सेवा के पहले मृत्यु हो जाय तो तीन माह की परिलब्धियों के समरूप उपदान दिया जायगा पर, उपरोक्त उपनियम (1) के तहत गणना की उपदान की राशि अगर यह अधिक हो तो भुगतान किया जाएगा।

3. अस्थायी कर्मचारी जिसे उपदान अधिनियम 1972 का भुगतान लागू नहीं होगा, सेवा के समय उसकी मृत्यु हो जाए या सेवा निवृत्ति हो जाय या अन्य किसी कारण से सेवा मुक्त कर दे जैसे कि अनुशासनिक कार्रवाई या दस वर्ष की लगातार सेवा के बाद त्याग पत्र दें तो उन्हें प्रत्येक समाप्त वर्ष के लिए एक महीने की परिलब्धियां की दर से उपदान किया जाएगा, बशर्ते कि अधिकतम निम्न प्रकार हो :

(अ) मृत्यु के मामले में 15 महीनों की परिलब्धियां या रु. 15,000 जो भी कम हो

(आ) अन्य मामलों में रु. 15000-

इन विनियम के तहत उपदान मंजूरी के लिए अध्याय 10 के तहत परिवार पेंशन योजना के लाभों को पाने से वंचित नहीं रहेगा, अगर अन्यथा पात्र हो।

उपरोक्त अधिनियम के तहत उपदान की मंजूरी तभी दी जाएगी जब कि उसके द्वारा की गयी सेवा में सक्षम प्राधिकारी जिसने उसकी नियुक्ति की हो संतुष्ट हों।

6. निम्न के लिए उपदान ग्राह्य नहीं है—

अ. ऐसे मामले जहां कर्मचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया या पोस्ट की सेवा से बरखास्त/निष्कासित किया गया हो

आ. परीक्षाधीन या अन्य कर्मचारी जो निर्धारित जांच या परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण पद से निकाल दिया गया हो और

इ. पुनः नियुक्त पेंशन भोगी

7. कोई कर्मचारी जो इस विनियम के तहत उपदान प्राप्त कर लेता है उसके अन्य उपदान व पेंशन लाभों को रोक दिया जाता है।

45. उपदान अधिनियम 1972 और उसके तहत बताये गये नियमों से शामिल कर्मचारियों को उपदान का भुगतान।

(1) उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें उपदान अधिनियम 1972 है उन्हें उपदान अधिनियम 1972 (1972 का अधिनियम) और समय-समय पर उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार उपदान दिया जाएगा। बशर्ते कि इनके निम्नलिखित बरती जाय।

(2) मूलभूत 9(21) के तहत विनिर्धारित वेतन जिसमें मंहगायी भत्ता, अतिरिक्त मंहगायी भत्ता, उजरत दर उपाजन प्रोत्साहन भत्ता तथा ऐसी अन्य अदायगी जो परिणाम योजना के तहत जहां भी लागू हो भुगतान किया जाए। उपदान के लघुकरण के प्रयोजन के लिए शामिल है। परंतु उजरत दर प्रोत्साहन और परिणाम योजना द्वारा वेतन की भुगतान आदि में शासित वर्गों के मामले में उनके रोजगार की समाप्ति के तुरंत तीन महीने या 10 महीने की अवधि के लिए उनके द्वारा प्राप्त कुल वेतन के औसत में लघुकरण किया जाएगा।

टिप्पणी : (1) वेतन समझौता दिनांक 4 जनवरी 1981 के अधीन वर्ग iii एवं IV कर्मचारियों को 1 जनवरी 1980 से देय विशेष स्थायी भत्तों की गणना वेतन के रूप में की जाएगी।

(2) अगर किसी कर्मचारी की सेवावधि में मृत्यु हो जाती है अथवा वह सेवा निवृत्ति से पूर्व अपनी तनाती से ऐसी छुट्टियों पर अनुपस्थित है जिनमें कि वह छुट्टी वेतन का हकदार है। अथवा सेवा के बिना समयहरण के साथ निरंतर से उसकी बहाली की गयी है तो उस अवधि में वह तनाती से पहले अनुपस्थित न होता या निरंतरित न होता तो उसके द्वारा गृहित परिलब्धियों उक्त विनियम के लिए परिलब्धियां मानी जाएगी।

परंतु वेतन बढ़ोतरी के कारण वेतन में कोई बढ़ावा हो या अन्यथा निवृत्ति पूर्व अर्जित छुट्टी के प्रथम 120 दिनों को लेख में न लेने के कारण उसकी परिलब्धियों में कोई घटाव नहीं होगा।

iii. (अ) उन कर्मचारियों के मामले में जो पांच वर्ष लगातार सेवा करने के उपरांत मर जाते हैं तो उनको देय उपदान बारह महीनों के वेतन से कम नहीं होगा।

आ. अगर कोई कर्मचारी एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष की सेवा की समाप्ति के पहले मर जायें तो उसकी उपदान राशि 6 महीनों के वेतन के बराबर होगी।

इ. अगर कोई कर्मचारी सेवा के प्रथम वर्ष में ही मर जाए तो देय उपदान की राशि दो महीनों के वेतन के बराबर होगी।

4. इस विनियम के तहत देय उपदान का विवरण नामांकन विधि आदि उपदान अधिनियम 1972 के तहत विनिर्धारित है और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार है।

5. शेष उपदान :—यदि कोई कर्मचारी जिसके लिए उपदान अधिनियम 1972 की अवायगी लागू होती है और जो पेंशन तथा सेवा निवृत्ति उपदान के लिए पात्र हो जाता है एवं उसके अपनी सेवा निवृत्ति की दिनांक से पूर्व पांच वर्ष के अन्दर मृत्यु हो जाती है (इसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति जो दण्ड के रूप में हो, शामिल है।) और उसकी मृत्यु के समय ऐसी उपदान अथवा पेंशन की उसके द्वारा प्राप्त वास्तविक रकम जिसमें तदर्थ वृद्धि भी शामिल है यदि कोई हो तथा इस रकम में इस विनियम के तहत ग्राह्य उपदान की राशि और लघुकृत राशि पेंशन के हिस्से की मूल्य के बराबर लघुकृत राशि उसकी परिलब्धियों के 12 वें हिस्से में कम है ता कमी वाली शेष उपदान की राशि उसके परिवार को भुगतान कर दी जाएगी।

अध्याय 10

परिवार पेंशन

46 (1) पेंशन योजना, द्वारा शासित किसी कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन का विनिर्धारित दरों पर भुगतान किया जाता है।

अ. उन कर्मचारी के परिवार के लिए जिन्होंने सेवा के समय एक वर्ष से कम लगातार सेवा न की हो।

आ. उस कर्मचारी के परिवार के लिए जो अनुकंपा भत्ता सहित पेंशन प्राप्त करता हो और निवृत्ति के बाद मर जाता हो।

(2) इन विनियम के प्रयोजन के लिए परिवार से तात्पर्य और परिवार के लोगों से तात्पर्य :—

अ. पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी या स्त्री कर्मचारी के मामले में पति परंतु इन सभी के मामलों में उनका विवाह कर्मचारी के सेवा निवृत्ति होने के पूर्व हुआ होना चाहिए।

आ. पति और पत्नी क्रमशः कानूनी तौर पर अलग हुए पति और पत्नी से तात्पर्य होगा।

ई. पुत्र जिसमें कानूनी तौर पर गोद लिया हुआ पुत्र भी शामिल है और जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो और अविवाहित पुत्री जिसमें कानूनी तौर पर गोद ली हुई पुत्री भी शामिल है और जिसकी आयु 24 वर्ष से कम हो।

टिप्पणी :—उपरोक्त अनुबंध में निवृत्ति के वाद्य जन्म लिए हुए पुत्र पुत्री शामिल नहीं होंगी।

47. परिवार पेंशन की दरें :—किसी कर्मचारी की सेवाकालीन मृत्यु होने पर या निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने पर परिवार को निम्न प्रकार से परिवार पेंशन दरें दी जाएंगी।

अ. वर्ग I व II अधिकारियों और वर्ग III और IV कर्मचारियों के मामले में जो विकल्प देते हैं उनके वेतन की परिभाषा विनियम 23(11) (ब) के तहत निम्नप्रकार से है :—

कर्मचारी की परिलब्धियां	परिवार पेंशन की मासिक राशि
रु. 400 से कम	परिलब्धियों की 30 प्रतिशत बशर्ते कि वह न्यूनतम रु. 60 और अधिकतम रु. 100/-
रु. 400 और उससे अधिक लेकिन 1200 से कम	परिलब्धियों की 15 प्रतिशत बशर्ते कि वह न्यूनतम रु 100 और अधिकतम रु. 160/-
रु. 200 और उससे अधिक	परिलब्धियों में 12 प्रतिशत बशर्ते कि वह न्यूनतम रु. 160 और अधिकतम 250 हो।

टिप्पणी : उपरोक्त दरों में से परिवार पेंशन की गणना के लिए परिलब्धियां विनियम 23 (ii) (ब) के तहत वेतन मानी जाएगी।

(9) वर्ग iii व IV के कर्मचारियों के मामले में जो विकल्प देते हैं उनके वेतन की परिभाषा विनियम 23 (11) (ब) के तहत निम्न प्रकार से हैं —

कर्मचारियों की परिलब्धियां	परिवार पेंशन की मासिक राशि
रु. 400 से कम	रु. 60
रु. 400 और उससे अधिक और रु. 800 से कम	रु. 100
रु. 800 से अधिक लेकिन 1200 से कम	वेतन का 12 प्रतिशत बशर्ते कि न्यूनतम रु. 100 हो
रु. 1200 से अधिक	रु. 160

टिप्पणी : परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों को वेतन माना जाएगा जैसा कि विनियम 23(II) (ब) तहत बताया गया है :—

(II) सेवा के समय मृत्यु होना :—

जहां कोई कर्मचारी कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के द्वारा शासित नहीं है या 7 वर्ष की लगातार सेवा के बाद कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय मृत्यु के अनुरूप कोई भी क्षतिपूर्ति प्राप्त न की हो तो उसके परिवार को दी जाने वाली परिवार पेंशन की दर सेवा के अंत में प्राप्त करने वाली परिलब्धियों की 50 प्रतिशत की समरूप होगी। या विनियम (1) के तहत सूचित दरों पर ग्राह्य कुमणी परिवार पेंशन जो भी कम हो और ऐसे ग्राह्य राशि का भुगतान कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक से आगे वाली दिन से 7 वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी या उस अवधि तक के लिए जब कि रोगी कर्मचारी 65 वर्ष तक जीवित रह सके जो भी पहले हो।

(1) जहाँ कोई कर्मचारी कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 द्वारा शासित हो या इस अधिनियम के तहत अनुरूप क्षतिपूर्ति के हकदार हो और 7 वर्ष की लगातार सेवा करने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी हो तो उसके परिवार को दय परिवार पेंशन की दर कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम परिलब्धियों की 50 प्रतिशत की समरूप होगी या उपरोक्त उपविनियम (1) के तहत ग्राह्य परिवार पेंशन में $1\frac{1}{2}$ गुणी होगी इसमें जो भी कम हो और इस तरह निर्णय किया गया पेंशन उपरोक्त खंड (अ) में बतायी गयी अवधि के अनुसार दी जाएगी।

टिप्पणी :—कोई कर्मचारी कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम द्वारा शासित होते हुए भी जहाँ उपरोक्त अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता तो परिवार पेंशन की दर उपविनियम (11) (अ) में बताये गये अनुसार होगा।

2. उपरोक्त विनियम (11) (अ) और (ब) के तहत प्राप्त अंतिम उपलब्धियों की 50 प्रतिशत को वेतन माना जाएगा जैसा कि विनियम 23 (ii) (ब) में परिभाषित किया गया है।

3. निवृत्ति के बाद मृत्यु :—

किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उसकी मृत्यु हो जाये तो उप विनियम (11) (अ) के तहत विनिर्धारित परिवार पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी या उस निवृत्त रोगी कर्मचारी की आयु 65 वर्ष तक होने की अवधि तक जो भी पहले हो।

परन्तु परिवार पेंशन की राशि किसी भी हालत में इस खंड के तहत विनिर्धारित राशि से ज्यादा न हो यानि कर्मचारी की निवृत्ति के समय मंजूर की गयी पेंशन के बराबर हो। पुनः उल्लेख किया जाता है कि इन सभी मामलों में ग्राह्य परिवार पेंशन की राशि, उपरोक्त उप विनियम (I) में बतायानुसार न्यूनतम परिवार पेंशन की दर पर होगी।

4. उपरोक्त उप विनियम के अनुसार बढ़ोत्तरी दर के परिवार पेंशन के भुगतान की अवधि की समाप्ति के बाद जैसा भी मामला हो, परिवार पेंशन परिवार के लोगों को उपविनियम (I) के तहत होगी।

टिप्पणी :—

- (1) अगर कोई कर्मचारी का बढ़ोत्तरी के समय में देहान्त हो जाये तो मृत्यु के पहले स्वीकृत सेवा की बढ़ोत्तरी दिनांक तक उसकी अधिवर्ष सामान्य दिनांक मानी जायेगी।
- (2) परिवार पेंशन की राशि मासिक दर से निर्धारित की जायेगी और पूर्ण रुपयों में बतायी जायेगी और जहाँ परिवार पेंशन अपूर्ण अंकों में पाई जायेगी उसे अगले पूर्णांक रुपयों में कर दिया जायेगा। परन्तु इस विनियम में विनिर्धारित न्यूनतम दरों से ज्यादा परिवार पेंशन किसी भी मामले में नहीं दी जायेगी।

(3) परिवार पेंशन की राशि को अंतिम स्तर पर ही पूर्णांक करना चाहिये। यानी प्रारंभ में गणना की गयी राशि को दुगुना करने के बाद।

48. देय परिवार पेंशन की अवधि निम्न प्रकार है :—

- (1) विधुर या विधवा के मामले में उसकी मृत्यु का पुनः विनियम तक जब भी पहले हो।
- (2) पुत्र के मामलों में उसके 21 वर्ष की आयु के होने तक और अविवाहित पुत्र के मामले में उसको 24 वर्ष की आयु होने तक या उसके विवाह तक जो भी पहले हो।
- (3) पति, पत्नी दोनों पोर्ट ट्रस्ट में काम करते हों और इस विनियम से शासित हों और इनमें से किसी एक की मृत्यु सेवा के समय या सेवा निवृत्ति के बाद हो जाये तो ऐसे मामलों में मृतक कर्मचारियों को परिवार पेंशन उनकी जीवित पत्नी या पति और उनकी मृत्यु पर जीवित बच्चों या बच्चों को परिवार पेंशन दिया जाता है। वशत कि निम्नलिखित निर्धारित सीमा पर होगी जैसे कि :—

(अ) अगर जीवित बच्चा बच्चे, विनियम 47(II) और (III) में बताये गये दर से दो परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं/हैं तो दोनों पेंशनों की राशि प्रतिमाह रु० 500 की सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

(आ) अगर विनियम 47(II) और बताये गये दर से देय एक परिवार पेंशन को काट दिया जाये तो विनियम 47(I) में बताये गये दर से पेंशन का भुगतान किया जायेगा। दोनों पेंशनों की राशि रु० 500 प्रतिमाह तक सीमित होगी।

(इ) अगर विनियम 47(I) में बताये गये दर से दोनों पेंशन का भुगतान किया जाता है तो दोनों पेंशनों की राशि रु० 250 प्रतिमाह तक सीमित-होनी चाहिये। परन्तु अगर किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट या अपाहित जो कुछ नहीं कर सकते या 21 वर्ष या 24 वर्ष के हो जाने पर भी जीविका पार्जन में असमर्थ हैं तो ऐसे पुत्र/पुत्री को परिवार पेंशन जीवन भर दिया जायेगा, वह निम्नलिखित शर्तों पर होगी जैसा कि—

- (1) अगर ऐसे पुत्र या पुत्री कर्मचारी के उन एक या दो बच्चों में से हों तो परिवार पेंशन, प्रारंभ में छोटे बच्चों को दिया जायेगा ताकि निम्न को ठीक किया जा सकें।
- (2) अगर एक से अधिक पुत्र या पुत्री मानसिक संतुलन खो बैठे हों और शारीरिक कमजोरियां

हों और अपाहिज हों, परिवार पेंशन निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा जैसा कि :—

पहले पुत्र को और अगर पुत्र एक या उससे अधिक हों तो दूसरे लड़के को पहले की मृत्यु के बाद और बाद में पुत्री को और अगर एक या उससे अधिक पुत्री हों तो दूसरे को पहली लड़की की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन दिया जायेगा ।

(3) अगर बच्चे नाबालिग हों तो परिवार पेंशन ऐसे पुत्र या पुत्री को उनके अभिभावक द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

(4) किसी भी पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन के भुगतान के पहले मंजूर प्राधिकारी इससे संतुष्ट होगा कि अपाहिज ऐसी प्रवृत्ति का हो कि वह अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो । इसको प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करें जो सिविल सर्जन से कम स्तर का न हो जिसमें बच्चे की वास्तविक मानसिक या शारीरिक दशा का वर्णन हो ।

(5) अभिभावक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे पुत्र या पुत्री के ठीक न होने तथा मानसिक असमर्थता से लगातार पीड़ित रहने या लगातार अपाहिज या शारीरिक असमर्थता रखना हो तो सिविल सर्जन के स्तर वालों चिकित्सा अधिकारी से तीन वर्ष में एक बार प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसे प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण :—(1) केवल ऐसी विकलांगता जो कर्मचारी के निवृत्ति या मृत्यु के पहले हो जाये तो इस विनियम के तहत परिवार पेंशन की मंजूरी के लिये लेखे पर लिया जायेगा ।

(2) इस उप विनियम के तहत अगर कर्मचारी की पुत्री का विवाह हो जाता है तो वह परिवार पेंशन की पात्रता को खो बैठती है ।

(3) अगर कर्मचारी का कोई पुत्र या पुत्री अपना जीविकोपार्जन करने लग जाते हैं तो उनको दी जाने वाली परिवार पेंशन रोक दी जायेगी ।

(4) ऐसे मामलों में अभिभावक को यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसे पुत्र या पुत्री अपनी जीविका के लिये कुछ नहीं कमा रहे हैं ।

(5) पुत्री के मामले में यह बताना जरूरी है कि वह अविवाहित है या नहीं ।

विधवा को छोड़ गये हों तो पेंशन दोनों को समान रूप से भुगतान किया जायेगा । एक विधवा की मृत्यु पर उसके छोटे बच्चों को वह पेंशन दी जायेगी । अगर किसी विधवा की मृत्यु के बाद उसकी कोई संतान न हो तो उसे दी जाने वाली पेंशन की हिस्सा रोक दिया जायेगा ।

(2) जहां कर्मचारी अपनी विधवा स्त्री को छोड़ जाये और दूसरी पत्नी को पात्र नाबालिक बच्चों को छोड़ गये हों तो पात्र नाबालिक बच्चे की पेंशन के हिस्से को उस बच्चे की मां प्राप्त करेगी ।

(3) इस विनियम के तहत टिप्पणियां (1) और (2) में बताये गये के अलावा एक ही समय में किसी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य से अधिक व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(4) अगर पुत्र और अविवाहित पुत्रियां हों तो परिवार पेंशन इन अविवाहिता पुत्रियों को तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पुत्रों की आयु 21 वर्षों की हो जाये, उसके बाद पुत्र परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते ।

(5) जहां मृतक कर्मचारियों पेंशन भोगी एक से ज्यादा बच्चे छोड़ गये तो उन में से सबसे बड़ा बच्चा 21 वर्ष की आयु तक परिवार पेंशन प्राप्त करेगा अगर बच्चा होता तो 24 वर्ष तक जैसा भी मामला हो और इन उपरोक्त आयु अवधि की समाप्ति के बाद दूसरे बच्चों को परिवार पेंशन की मंजूरी दी जायेगी ।

(6) विधवा या विधुर के पुनः विवाह करने पर या मृत्यु हो जाने पर उनके नाबालिग बच्चों को उनके प्राकृतिक अभिभावकों द्वारा परिवार पेंशन का भुगतान किया जायेगा । अन्यथा अगर उनके किसी कानूनी अभिभावकों द्वारा दी जाये तो उन्हें क्षतिपूर्ति बंध प्रस्तुत करना होगा । जैसा कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय की का.शा.सं. एफ 10(3) ई बी (ए) 61 दिनांक 29 जून 1961 में बताये गये आदेशों के अनुसार होगा । परन्तु सरकारी मामलों में कानूनी अभिभावकों द्वारा भुगतान किया जायेगा यानि कि उपरोक्त का.शा. में बताये गये अनुदेशों के अनुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावकों द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

कानूनी तौर पर अलग किये गये पति या पत्नी परिवार पेंशन के लाभों को पाने के लिये कर्मचारी की पति/पत्नी की कानूनी हैसियत नहीं खोयेगा/खोयेगी ।

49. पारिवारिक विवरणों का प्रस्तुतीकरण :—सभी कर्मचारियों जो इन विनियमों के लाभों को पाने के हकदार हैं उन्हें विनियम 46 के उपविनियम (ii) में परिभाषित के अनुसार परिवार के विवरणों को देना होगा । उसके बाद कर्मचारी को इस विवरणिका को अद्यतन बनाये रखना होगा । संबंधित कर्मचारी से सूचना और आधारित प्रपत्रों के प्राप्त होने के बाद समय समय पर विभाग के प्राधिकृत संबंधित अधिकारियों द्वारा विवरणिका में संशोधित करनी चाहिये ।

टिप्पणी : 1) परिवार पेंशन के परिणाम में पेंशन लघुकरण का प्रभाव ।

परिवार पेंशन के परिणाम पर पेंशन के लघुकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि परिवार पेंशन की दर कर्मचारी की तुरन्त निवृत्ति से पहले प्राप्त वेतन के आधार पर होगी न कि मंजूर की गयी पेंशन के आधार पर।

(2) परिवार पेंशन की पात्रता को निर्धारित करने के लिये छुट्टी सेवा की अवधियों की गणना

इन विनियमों के तहत एक वर्ष की सेवा अवधि सेवा के रूप में नहीं निर्धारित की जायेगी। इसके प्रयोजन के लिये सेवा जारी रहेगी।

अध्याय 9 नामांकन

50. नामांकन से संबंधित प्रावधान जो इस अध्याय में उल्लिखित हैं वे उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनके लिए "उपदान अधिनियम 1972 लागू नहीं होते।

परिवार

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए परिवार किसी कर्मचारी के अर्थ में :—

- (1) पुरुष कर्मचारियों के मामले में पत्नी या पत्नियों में कानूनी तौर पर अलग की हुई पत्नी या पत्नियां भी शामिल हैं।
- (2) स्त्री कर्मचारियों के मामले में पति जिनमें कानूनी तौर पर अलग किए गए पति भी शामिल हैं।
- (3) पुत्र जिनमें सौतेले पुत्र और दत्तक पुत्र भी शामिल हैं।
- (4) अविवाहित पुत्रियां जिनमें सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं।
- (5) पिताजी जिनमें दत्तक जन्मदाना भी शामिल है ऐसे मामले जिनकी दत्तक के लिए व्यक्तिगत कानून स्वीकार करते हैं।
- (6) माता जिनमें दत्तक माता भी शामिल है ऐसे व्यक्तिगत के मामले में जिन्हें कानून दत्तक के लिए स्वीकार करते हैं।
- (7) भाई जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो जिनमें सौतेले भाई भी शामिल हैं।
- (8) अविवाहित बहनें और विधवा बहनें जिनमें सौतेली बहनें भी शामिल हैं।
- (9) विवाहित पुत्रियां और
- (10) मृतक पुत्रों के बच्चे।

भनोतयन

51. (1) कोई कर्मचारी अपनी सेवा के समय या पद पर स्थायी होते समय प्रारंभ में विनिर्धारित प्रावधानों में नामांकन करेगा जिसमें विनियम 40 के

तहत देय मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए एक या उससे अधिक व्यक्तियों को नामित किया जाना चाहिए।

परन्तु नामांकन के समय निम्नलिखित का होना जरूरी है।

- (अ) अगर कर्मचारी का परिवार है तो नामांकन परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/व्यक्तियों पर नहीं होना चाहिए।
- (आ) अगर कर्मचारी का परिवार न हो तो किसी व्यक्ति/व्यक्तियों या वैयक्तिक निकाय अगर वह शामिल हो या न हो, पर नामांकन किया जाना है।
- (2) अगर विनियम (1) के तहत एक या एक से अधिक व्यक्तियों को देय राशि के अंश को निर्धारित करेगा ताकि उपदान की पूर्ण राशि उसमें समा सके।
- (3) कर्मचारी अपने नामांकन में निम्नलिखित का जिक्र करेगा जैसा कि :—

नामांकन में नामित कोई व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के पहले ही मर जाए या कर्मचारी की मृत्यु के बाद मर जाए लेकिन उपदान राशि न प्राप्त की हो तो इस नामित व्यक्ति का अधिकार नामांकन में दर्शाए गए दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा।

परन्तु कर्मचारी नामांकन करने समय उसके परिवार में एक से अधिक सदस्य हो और वह व्यक्ति परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति न हो।

फिर कहा जाता है कि जहां कर्मचारी परिवार में एक ही सदस्य हो और उसे नामित किया गया हो तो दूसरे नामांकन के लिए अन्य कोई व्यक्ति निकाय जो कर्मचारी से संपर्क रखता हो या न रखता हो, नामित करेगा।

व. प्रावधानों में बनावे गये अनुसार न होने पर नामांकन अवैध घोषित किया जाएगा।

4. कर्मचारी द्वारा दिया गया नामांकन जिसका परिवार न हो या कर्मचारी द्वारा उपविनियम (iii) के खंड (अ) की दूसरी धारा के तहत बनावे गये नामांकन जहां उसके परिवार में एक ही सदस्य हो तो वह नामांकन नब अवैध हो जाएगा जब कर्मचारी का परिवार बन जाए या परिवार में अतिरिक्त सदस्य आ जाए जैसा भा. मामला हो।

5. कर्मचारी किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित रूप में देकर नामांकन को रद्द कर सकता है। परन्तु इस विनियम के अनुसार नये नामांकन की प्रति साथ भेजेगा।

6. नामित व्यक्ति की तुरंत मृत्यु के बाद जिसके लिए उप विनियम (iii) खंड (अ) के तहत नामांकन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं या किसी अन्य कारण से उक्त उपविनियम खंड (अ) के तहत नामांकन अवैध हो जाता है तो कर्मचारी लिखित में

लेखा अधिकारी को पाम नामांकन रद्द करने के लिए पत्र देगा साथ ही इस विनियम के अनुसार नया नामांकन भी देगा।

7. प्रत्येक नामांकन या उसके रद्दीकरण की सूचना अधिका-री को विभागाध्यक्ष के जरिए भेजेगा और अगर वह ठीक हो तो हस्ताक्षर व तिथि लगाकर अपने पाम रख लेगा।
8. जो भी नामांकन या रद्दीकरण कर्मचारी द्वारा किया जाता वह लेखा अधिकारी के स्वीकृत दिवस से लागू होगा।

अध्याय 12—सामान्य शर्तें

52. पेंशन या परिवार पेंशन के दावों के विनियम :—

- (1) कर्मचारी के निवृत्त हो जाने या निष्कासित होने या सेवा से त्याग पत्र देने पर या उसकी मृत्यु हो जाए जैसा भी मामला हो तो पेंशन या परिवार पेंशन के दावों को इन विनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाएगा।
- (2) कर्मचारी जिस दिन सेवा निवृत्त हुआ हो, निवृत्त हो रहा हो या निष्कासित हो या त्याग पत्र दे दिया हो या उसकी मृत्यु हो गयी हो वही उसका अंतिम कार्यदिवस माना जाएगा। परन्तु अगर कोई कर्मचारी सेवा अवधि से पहले निवृत्त हो जाए या मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (निवृत्ति) विनियम के तहत स्वेच्छा से निवृत्त हो जाय तो ऐसे मामले में निवृत्त होने के दिनांक के गैर कार्य दिवस माना जाएगा।
- (3) पेंशन, परिवार पेंशन सहित उस दिन के लिए देय होगा जिस दिन प्रापक की मृत्यु होती है।
- (4) अध्याय 10 में ग्राह्य परिवार पेंशन के अलावा इस विनियम के तहत पूर्ण पेंशन की मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक की गयी सेवा संतोषप्रद मानी जाती है।

53. सेवा के संतोषप्रद न होने पर पेंशन की राशि में कमी (1) अगर कर्मचारी के निवृत्ति के दिनांक के पूर्व उसके द्वारा की गयी सेवा संतोषप्रद न हो तो अध्यक्ष जैसा ठीक रूप पेंशन या उपदान की राशि में कमी करने का आदेश देगा।

परन्तु अध्यक्ष इस उपविनियम के तहत आदेश देने के पूर्व उस कर्मचारी को सेवा की असंतुष्टता के कारण राशि में की गयी कमी की सूचना देगा और ऐसे व्यक्ति से 15 दिन के भीतर या जितना भी समय उसे दिया गया हो उसके भीतर अगर वह इसके विपक्ष में कुछ कहना चाहे तो आदेश पारित होने के पूर्व लिखित रूप में उसका अभ्यावेदन प्राप्त कर लेना होगा।

अग्रे बताया जाता है कि विनियम 26 के टिप्पण 5 में बताये गये अनुसार पेंशन राशि के सीमा में कम नहीं घटाया जाएगा।

2. अ. उप विनियम 1 में बतायी गयी कमी स्थाई प्रकृति की होगी।

(ब) पेंशन की राशि में कमी उस हद तक की जाएगी जब तक कर्मचारी अपनी पूर्ण सेवा संतोषप्रद की हो और राशि को सम बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी या बोर्ड को हुई क्षति की राशि के बराबर कमी नहीं की जाएगी।

3. किसी व्यक्ति की पेंशन को प्राधिकरण करने के पश्चात अध्यक्ष को यह सूचना मिले कि उसकी सेवा संतोषप्रद नहीं है तो इन विनियमों के तहत प्राधिकृत पेंशन में कोई कमी नहीं की जायगी।

4. विनियम में निम्नलिखित लागू नहीं होंगे।

अ. जहां पेंशन के एक अंश को रोका गया हो या विनियम 56 के तहत बसूल के लिए आदेश हो।

आ. जहां मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान विनियम 40(2) के तहत ग्राह्य हो और परिवार पेंशन देय हो।

इ. दंड के परिणामस्वरूप कोई बसूनी हो तो उसे लागू करना

ई. जहां विनियम 10 के तहत पेंशन का अंश कम किया गया हो।

54. पेंशन की संख्या में सीमाएं :— कोई कर्मचारी अगर अधिवर्षियता पर निवृत्त हो या निवृत्त हो रहा हो तो उसे पुनः कार्यभार संभालने की अवधि के लिए पेंशन व उपदान नहीं दिया जाएगा।

55. भावी अच्छे आचरणों पर पेंशन :— अगर पेंशन भोगी भारी जुर्म में बंदी बना दिया गया हो या भारी दुराचार से दोषी साबित हुआ हो तो अध्यक्ष, उसकी दी जाने वाली पूर्ण या आंशिक पेंशन को स्थाई रूप में या विनिर्धारित अवधि के लिए रोक सकता है या वापस ले सकता है।

इन विनियमों तहत पेंशन की प्रत्येक अदायगी और उसके जारी रहने के लिए भावी अच्छे आचरण अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु जहां पेंशन का कोई भाग रोक या वापस ले लिया जाता है वह पेंशन की न्यूनतम सीमा से कम नहीं होना चाहिए।

11. जहां कर्मचारी न्यायालय द्वारा भारी जुर्म के कारण बंदी बना दिया जाता है तो ऐसे बंदी के संबंध में न्यायालय के निर्णय के आधार पर उप विनियम 1 (ब) के तहत कार्रवाई की जायगी।

3. ऐसा मामला जो उप विनियम 2 के तहत नहीं आता और उप विनियम 1(ख) में उद्धृत प्राधिकारी ऐसा महसूस करता है कि पेंशनर प्रत्यक्षतः गंभीर दुराचार का दोषी है तो वह उप विनियम 1(ख) के तहत आदेश जारी करने से पहले —

क. पेंशनर को उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी करेगा तथा उक्त कार्रवाई का कारण भी बतायेगा तथा नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अथवा ऐसे आगे के समय तक जो 15 दिन से अधिक न हो जैसा कि अध्यक्ष अनुभव करें, ऐसा अभ्यावेदन करने के लिए कहेगा, जैसा कि वह उक्त कार्रवाई के प्रसव के खिलाफ उचित समझे।

ख. खंड क के तहत पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए अभ्या-वेदन यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

4. इस विनियम के उप विनियम 1 (ख) के तहत किये गये आदेशों के खिलाफ अपील बोर्ड को की जायेगी तथा बोर्ड अपील पर ऐसे आदेश जारी करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

56. पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार—

1. पेंशन रोकने या वापस लेने अथवा इसके किसी भी भाग को रोकने या वापस लेने चाहे स्थायी रूप से या विनिर्धारित अवधि तक के लिए अध्यक्ष को स्वयं पूर्ण अधिकार है, तथा कर्मचारी के अपनी सेवा अवधि में जिसमें सेवानिवृत्ति होने पर पुनः रोजगार में आने की सेवा भी शामिल है गंभीर दुराचार या लापरवाही के कारण विभागीय का न्यायिक कार्रवाई से दोषी पाया जाता हो और उसमें बोर्ड को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो पेंशन के उक्त नुकसान को संपूर्ण या उसके अंश की वसूली के लिए अध्यक्ष आदेश जारी कर सकते हैं।

परन्तु जहां पेंशन का भाग रोक जाता है या वापस लिया जाता है तो इस प्रकार की पेंशन की रकम न्यूनतम ग्रह सीमा से कम नहीं की जायेगी।

2. विभागीय कार्रवाई जब कर्मचारी सेवा में या शुरू नहीं की गई हो चाहे उसको सेवा निवृत्ति के बाद या पुनः रोजगार के दौरान

क. तो उक्त कार्रवाई अध्यक्ष या बोर्ड यथास्थिति की मंजूरी के बिना शुरू नहीं की जायेगी।

ख. ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले चार वर्ष की अवधि के दौरान हुई किसी घटना के मामले और

ग. ऐसी कार्रवाई जिस पर कि सेवा से बरखास्तगी के आदेश जारी किये जा सकते हैं, के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर यह कार्यवाही शुरू की जायेगी जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें

3. ऐसी कार्रवाई के प्रारम्भ होने से चार वर्ष की घटना के बाद अथवा कार्रवाई पर उत्पन्न कारणों पर न्यायिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जायेगी अगर यह कर्मचारी के सेवाकाल में प्रारम्भ न की गई हो चाहे उसके सेवा-निवृत्ति होने से पहले या पुनः रोजगार में आने पर।

व्याख्या—इस विनियम के प्रयोजनार्थ—

1. पेंशनर के खिलाफ लगाये गये आरोपों को उसे जारी करने के बाद या अगर कर्मचारी पूर्व तिथि से निलम्बित किया गया है तो उस दिनांक से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ मानी जायेगी और

2. न्यायिक कार्यवाही निम्न प्रकार से प्रारम्भ मानी जायेगी —

1. अपराधी प्रक्रिया के मामले में उस दिनांक से जिसको कि शिकायत की गई है या उस दिनांक को जिसको कि आरोप-पत्र अपराधी न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है और

2. सिविल प्रक्रिया के मामले में उस दिनांक से जिसको कि शिकायत प्रस्तुत की गयी हो या सिविल न्यायालय को आवेदन पत्र भेजा गया हो उस दिनांक से यथास्थिति।

3. ऐसे मामलों में जहां अध्यक्ष तय करते हैं कि पेंशन न तो रोक जाये, न ही वापस की जाये परन्तु कर्मचारी द्वारा किये गये आर्थिक नुकसान के लिये पेंशन से वसूली का आदेश देते हैं तो कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति होने के दिनांक को उसे ग्राह्य पेंशन की 1/3 से अधिक रकम की वसूली नहीं की जायेगी।

57. मंजूरी के बाद पेंशन की पुनरीक्षा—

1. अन्तिम मूल्यांकन के बाद एक बार मंजूर की गई पेंशन के बाद कर्मचारी को नुकसान होने की वजह से उस की पुनरीक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी पुनरीक्षा लिपिकीय गलती के कारण आवश्यक न हो।

परन्तु अगर पेंशन की मंजूरी के दो वर्ष बाद लिपिकीय गलती मालूम होती हो तो अध्यक्ष की मंजूरी के बिना पेंशनर को होने वाले नुकसान के लिये पेंशन की पुनरीक्षा नहीं की जायेगी।

2. उपविनियम (1) के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कर्मचारी को इस बात का नोटिस जारी किया जायेगा कि उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के अन्दर उसे की गई अधिक अदायगी को वह वह वापस कर दे।

3. अगर कोई कर्मचारी नोटिस का पालन नहीं करता हो तो पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी लिखित रूप से इस बात का निदेश दे सकता है कि भविष्य में एक या अधिक किशतों में जैसा निर्णय करे पेंशन की कम अदायगी करके अधिक अदायगी का समंजस कर दिया जाय।

58. पेंशन पाना (पेंशनर के इच्छानुसार)

निम्न किसी भी ढंग से उसकी अदायगी की जा सकती है।

1. लेखा अधिकारी के कार्यालय से नकद
2. पेंशनर के खर्च पर डिमांड ड्राफ्ट/बैंक द्वारा
3. डाक मनी ऑर्डर रु. 100/- तक की पेंशन पेंशनर को ट्रस्ट के खर्च पर भेजी जायेगी।
4. अधिसूचित विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा।
59. रद्द और समपहरण—

अगर पेंशन एक वर्ष की अधिक अवधि से नहीं निकाली गयी है तो इसकी अदायगी रोक दी जायेगी परन्तु इसके पश्चात् अगर पेंशनर लेखा अधिकारी के पास जाता है तो वह उसका नवीकरण कर सकता है।

60. पेंशनर की मृत्यु के बाद पेंशन के बकाया की अदायगी—

पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् उसके वास्तविक देय पेंशन की बकाया राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को कर दिया जायेगा।

बशर्ते कि वे उसकी मृत्यु के एक वर्ष पूर्व आवेदन करें। उसके पश्चात् अध्यक्ष की मंजूरी के बिना इसकी अदायगी नहीं की जायेगी।

अध्याय—13—विविध

61. पेंशन मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी पेंशन मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी

1. वर्ग 1 के अधिकारियों के मामले में अध्यक्ष,
2. वर्ग 2 के अधिकारियों के मामले में उपाध्यक्ष
3. वर्ग 3 व 4 के मामले में लेखा अधिकारी

62. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ पेंशन की प्रक्रिया पेंशन का लघुकरण उपदान एवं परिवार पेंशन तथा उसके लिये अपेक्षित फार्मस आदि वही होंगे जैसा कि समय पर अध्यक्ष निर्धारित करें।

63. 1. इन विनियमों के पूर्ववर्ती प्रावधानों को लागू करने में और ऐसे मामलों जो उक्त विनियमों के तहत नहीं आते उनके लिये केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियम लागू होंगे।

परन्तु ये ऐसे अपवाद और बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किये गये संशोधनों के अनुसार लागू होंगे।

2. अगर केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के मामले में मीजब लाभों की उदार बनाती है या संशोधन करती है तो इन विनियमों के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसी उदारता या संशोधन, ऐसी शर्तें अपवाद और संशोधन जैसा कि आवश्यक हों, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा तय करने पर ही लागू होंगे।

अगर ऐसी उदारता या संशोधन कर्मचारियों के लिये लागू किये जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा जब तक कि अन्यथा तय न किया गया है। इन विनियमों के औपचारिक संशोधन होने तक उस दिनांक से लागू होंगे जिससे केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये लागू किया हों।

64. बोर्ड लिखित रूप से संकल्प निर्धारित कर सकता है कि इन विनियमों में बोर्ड को प्रदत्त अधिकारों में से कौन-सा अधिकार अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं तथा ऐसे किसी भी संकल्प को रद्द या बदल सकते हैं।

65. अनुग्रह पूर्वक पेंशन—ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 1963 से पहले 20 साल की लगातार सेवा पूरी करके अंशदायी भविष्य निधि पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं तथा इस कारण उन्हें पेंशन के लाभों को अपनाने का मौका नहीं मिल पाता हो ऐसे कर्मचारियों को 1 जनवरी 1967 से निम्न लिखित प्रकार से अनुग्रह पूर्वक पेंशन प्रदान की जायेगी।

सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा गृहीत वेतन	अनुग्रह पूर्वक पेंशन की राशि	
	1 जनवरी 1967 से	1 फरवरी 1972 से
	रु. पै.	रु. पै.
क. प्रति माह रु. 80/- या कम	15.00	25.00
ख. प्रति माह रु. 80/- से अधिक अधिक तथा रु. 130/- तक	17.50	27.50
ग. प्रति माह रु. 130 से अधिक तथा रु. 200 तक	20.00	30.00
घ. प्रति माह रु. 200 से अधिक तथा रु. 500 तक	22.50	32.50

(2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें सेवा से बरखास्त किया जाता है या निकाला जाता है तथा जो सेवा से त्याग पत्र देते हैं उन्हें यह पेंशन ग्राह्य नहीं होगी।

(3) दिनांक 1 जनवरी 1973 से अनुग्रह पूर्वक पेंशन पाने वाले को केन्द्रीय सरकार ने तबत राहत प्रदान की है अतः यह अदायगी उसी दिनांक से ट्रस्ट कर्मचारियों को

भी प्रदान की जायेगी तथा उन्हीं शर्तों पर होगी जैसी कि केन्द्रीय सरकार के अनुग्रह पूर्वक पेंशनर्स के लिये है।

टिप्पणी :—द्वितीयो निम्नलिखित दर से की गई है।

निवृत्ति के दिनांक कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन	1-1-73	1-8-73	1-1-74	1-4-74	1-10-75	1-4-77	1-9-77	1-12-78
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रु. 80 या उससे कम	15	5	5	5	10	5	5	5
रु. 80 से अधिक और रु. 130 तक	15	5	5	5	10	5	5	5
रु. 130 से अधिक और रु. 200 तक	15	5.50	5.50	5.50	11	5.50	5.50	5.50
रु. 200 से अधिक और रु. 500 तक	21	9	9	9	18	9	9	9

पेंशन भुगतान की विधि समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों के अनुसार मंजूरी तथा अनुग्रहपूर्वक पेंशन के भुगतान के लिये भी लागू होगी।

प्रशासनिक कार्यालय भवन,
राजाजी रोड,
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट,
मद्रास-600 001
दिनांक 29-4-1987

अशोक जोशी

अध्यक्ष

हिन्दी आधिकारी

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट
मद्रास

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd May, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 523(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust (Pension) Regulations, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the Schedule annexed to this notification.

The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12018/9/86-PF-II

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

THE SCHEDULE

MADRAS PORT TRUST

Madras Port Trust Pension Regulations

(RRC/17334/86/S)

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963),

the Madras Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Government, the following draft regulations in supersession of the existing Madras Port Trust Pension Rules and the same is published herein as required under section 124 of the said Act :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(i) These regulations shall be called the Madras Port Trust Pension Regulations, 1987.

2. Application.—These regulations shall apply to—

(i) employees governed by the Madras Port Trust Pension Rules.

(ii) all persons including Shore Labour appointed.

(iii) other employees who may be permitted to opt for pension from time to time.

3. Definitions.—In these regulations unless the context otherwise requires—

(i) 'Accounts Officer' means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or such other officer of the Accounts Department as may be prescribed by the Chairman;

(ii) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(iii) 'Average emoluments mean's average determined in accordance with Regulation 24;

(iv) 'Board Chairman', 'Deputy Chairman' and 'Head of Department' shall have the meaning assigned to them under the Act;

(v) 'Child' means a child of the employee, who, if a son, is under twenty one years of age and if a daughter is unmarried and is under twenty-four years of age and the expression 'Children' shall be construed accordingly;

(vi) 'Chief Medical Officer' means the Chief Medical Officer of the Board;

(vii) 'Emoluments' means emoluments defined as such under Regulation 23;

(viii) 'Employee'.—The words permanent and temporary employee shall have the meaning assigned to them in the Madras Port Trust Employees (Appointment, Promotion etc.) Regulations;

(ix) 'Family Pension' means a pension payable to the family of an employee who dies while in service or after retirement as the case may be;

(x) 'Foreign Service' means in service in which an employee receives his pay with competent sanction from any source other than the funds of the Madras Port Trust;

(xi) 'Gratuity' means Gratuity payable under Chapter IX;

(xii) 'Leave' means any kind of leave reckoned by the Fundamental Rules of the Government of India or the Leave Regulations framed by the Board which may be applicable to the employee from time to time;

(xiii) 'Minor' means a person who has not completed the age of eighteen years;

(xiv) 'Pension' includes gratuity except when the term pension is used in contradistinction to gratuity;

(xv) 'Qualifying service' means service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pensions and gratuities admissible under these regulations;

(xvi) 'Retirement benefit' means pension and gratuity;

(xvii) 'Service' means the period of the employment from the date of its commencement to the date of its quitting and includes all periods of leave with or without pay.

CHAPTER II—CLASSES OF PENSION AND CONDITIONS GOVERNING THEIR GRANT.

4. Pension falls under the following classes :—

- (i) Superannuation Pension.
- (ii) Retiring Pension.
- (iii) Invalid Pension.
- (iv) Compensation Pension.
- (v) Compassionate Allowance.
- (vi) Compulsory Retirement Pension.

5. Superannuation Pension—A superannuation pension shall be granted to an employee who retires on his attaining the age of compulsory retirement.

6. Retiring Pension—A retiring pension is granted to an employee who retires or is retired in public interest in advance of the age of retirement in accordance with the Madras Port Trust Employees' (Retirement) Regulations.

7. Invalid Pension—(i) An invalid pension may be granted if an employee retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service.

(ii) An employee applying for an invalid pension shall submit a Medical Certificate of incapacity from the Chief Medical Officer.

(iii) The form of Medical Certificate shall be as may be prescribed.

(iv) Where the Chief Medical Officer has declared an employee fit for further service of less labourious character than that which he had been doing he should, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even in a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(v) If the incapacity is directly attributable to irregular or intemperate habits of an employee, no invalid pension shall be granted. The decision of the Chairman in this regard shall be final.

(vi) If incapacity has not been directly caused by such habits, but had merely been accelerated or aggravated by them, it shall be for the Chairman to decide what reduction should be made on this account.

8. Compensation Pension—If an employee is selected for discharge owing to the abolition of his permanent post, he shall, unless he is appointed atleast to another equivalent post have the option of—

(i) taking any compensation pension to which he may be entitled for the service he has already rendered; or

(ii) accepting another appointment on such pay as may be offered and continuing to count his previous service for pension.

(iii) If a person who is entitled to Compensation Pension accepts instead another appointment and subsequently becomes entitled to receive a pension of any class, the amount of such pension shall not be less than the Compensation Pension which could have been claimed if he would not have accepted the appointment.

9. Compassionate Allowance :—An employee who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension :

Provided that to an employee so dismissed or removed, in deserving cases a compassionate allowance of not less than the minimum pension and not exceeding two-thirds of pension which would have been admissible to him, if he had retired on Compensation Pension, may be granted.

10. Compulsory Retirement Pension :—An employee compulsorily retired from service as a penalty may be granted, a pension or gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement, subject however to the minimum pension admissible under these regulations.

CHAPTER III

11. Conditions for eligibility for Pension—The following conditions must be fulfilled by an employee governed by these Regulations to be entitled to Pension :

- (i) He must have completed a minimum qualifying service of not less than 10 years.
- (ii) The service must be substantive or permanent.

CHAPTER IV—QUALIFYING SERVICE FOR PENSION

12. Commencement of qualifying service—(i) Qualifying service of an employee shall commence from the date of his taking charge of the post to which he is first appointed, either substantively or in an officiating or temporary capacity :

Provided that in the case of officiating or temporary service including service as a Probationer it should be followed without interruption by substantive appointment in the same or another post;

(ii) Service rendered before attaining the age of eighteen years shall not count as service qualifying for pension except for compensation gratuity;

(iii) Casual service shall not count for pension.

13 Counting of service as apprentice—Service as an apprentice shall not qualify for pension.

14. Counting of periods spent on leave—all leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate shall count as qualifying service :

Provided that in the case of "Extraordinary Leave" other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to an employee—

(i) Due to his inability to join or rejoin duty is account of civil commotion ; or

(ii) For prosecuting higher scientific and technical studies.

15. Counting periods under suspension—Time passed by an employee under suspension pending enquiry into a conduct shall count as qualifying service where on conclusion of such enquiry, he has been fully exonerated of the suspension is held to be wholly unjustified; in other cases, the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the regulations governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as that authority may declare.

16. FORFEITURE OF SERVICE DISMISSAL OR REMOVAL—Dismissal or removal of an employee from service or post entails forfeiture of his past service.

17. FORFEITURE OF SERVICE ON RESIGNATION—Resignation from service or a post, unless it is allowed to the withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails of past service except for the purpose of payment of gratuity under Regulation in Chapter IX in respect of employees to whom the Payment of Gratuity Act, 1972 and the rules framed thereunder apply.

18. COUNTING OF PAST SERVICE ON RE-INSTATEMENT—(i) An employee who is dismissed, removed or compulsorily retired from service, but is reinstated on appeal or review, is entitled to count as past service as qualifying service.

(ii) The period of interruption in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement.

19. ADDITIONS TO QUALIFYING SERVICE IN SPECIAL CIRCUMSTANCES—An employee appointed to a post shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension, but not for any other class of pension) the actual period not exceeding one fourth of the length of service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded twenty-five years or a period of five years, whichever is less, if the post to which he is appointed is one—

(i) to which candidate of more than twenty-five years of age are normally recruited ;

(ii) for which post-graduate research or specialist qualification or experience in scientific, technological or professional fields is essential ;

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time he quits service is not less than ten years.

NOTE.—The Administration should identify such posts with reference to the age or professional experience prescribed for direct recruitment to the said posts in the manner of appointment.

20. EFFECT OF INTERRUPTION IN SERVICE—An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past service, except in the following cases :—

(i) Authorised leave of absence :

(ii) Unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of absence is not filled substantively ;

(iii) Suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or different post or where the employee dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement while under suspension ;

(iv) transfer to non-qualifying service.

21. Commutation of periods of absence without leave into extraordinary leave.—The appointing authority may commute retrospectively periods of absence without leave into leave without allowance.

22. Condonation of interruption in service.—(i) The appointing authority may, by order, condone interruption in the service of an employee ;

Provided that :—

(a) the interruption has been caused by reasons beyond the control of the employee ;

(b) the total service excluding one or more interruption, if any, is not less than five years duration ; and

(c) the interruption, including two or more interruptions, if any, does not exceed one year ;

(ii) The period of interruption condoned under this sub-regulation shall not count as qualifying service.

CHAPTER V—EMOLUMENTS AND AVERAGE EMOLUMENTS

23. Emoluments.—(i) In respect of employees belonging to Class I or cadres, the expression emoluments means 'Pay' as defined in F.R. 9 (21) and Dearness Pay as may be determined from time to time which the class I or II Officer was receiving immediately before his/her retirement or on the date of his/her death.

(ii) In respect of a Class III or IV employee emoluments means any one of the following which he/she was receiving immediately before retirement or on the date of his/her death as he/she may opt :—

(a) Pay as defined under F.R. 9(21), Dearness Allowance including Additional Dearness Allowance, Piece Rate earnings, Incentive earnings and other such payments under a Payment by Result Scheme wherever applicable, or

(b) Pay as defined under F.R. 9(21), Piece Rate Earnings, Incentive Payments and other such payments under a Payment by Result Scheme wherever applicable.

NOTE.—(1) The Special Fixed Allowance payable from 1st January 1980 to classes III and IV employees under the wage settlement dated 4th January 1981 will be reckoned as pay both under (a) and (b).

(2) The option for the 'emoluments' must be exercised by the employee one month before the date of his retirement or quitting service. In respect of employees who die while in service, the option can be exercised by the family before settlement of accounts.

(iii) If an employee immediately before retirement or death while in service, had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be the emoluments for the purpose of this regulation:

Provided that any increase in pay either on account of increment or otherwise not accruing during the first 120 days of Earned leave Preparatory to retirement first shall not form part of his emoluments.

(iv) Where the employee immediately before his retirement or death while in service had proceeded on leave for which leave salary is payable after having held a higher appointment whether in an officiating or temporary capacity, the benefit of emoluments drawn in such higher appointment shall be given only if it is certified that the employee would have continued to hold the higher appointment but for his proceeding on leave.

(v) If an employee immediately before his retirement or death while in service has been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension, the period whereof does not count as service, the emoluments which he drew immediately before proceeding on such leave or being placed under suspension shall be the emoluments for the purpose of this regulation:

(vi) In respect of employee on Foreign Service the emoluments which they would have drawn under the Trust had they not been on Foreign Service shall alone be treated as emoluments.

(vii) In respect of categories governed by a Piece Rate/Incentive/Payment by Results Scheme, emoluments for the purpose of Gratuity and family pension mean the emoluments as defined in sub-regulation (ii) supra or the average of the emoluments as defined in Regulation 24 whichever is advantageous to the employee.

(viii) In respect of an employee with a substantive appointment who officiates in another appointment or holds a temporary appointment, emoluments means—

(a) the emoluments which would be taken into account under this regulation in respect of the appointment in which he officiates or of the temporary appointment as the case may be, or

(b) the emoluments which would have been taken into account under this regulation had he remained in his substantive appointment whichever is more favourable to him.

24. Average Emoluments.—(i) The term average emoluments shall mean the average of the emoluments earned by an employee during 10 complete months immediately preceding the date of quitting service or the date of his death as the case may be.

(ii) If during the last 10 months of service the employee had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments shall be the emoluments for the purpose of this regulation:

luments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be taken into account subject to provision in regulation 23.

(iii) If during the last 10 months of his service employee had been absent from duty on extraordinary leave, or had been under suspension the period, whereof does not count as service, the aforesaid period of leave or suspension shall be disregarded in the calculation of the average emoluments and equal period before 10 months shall be included.

NOTE.—In respect of categories governed by a Piece-Rate|Payment by Result|Incentive Scheme, if during the last 10 months immediately preceding the date of quitting service or death. The employee was on leave continuously the average shall be calculated as indicate above, subject however that in respect

of Piece-Rate|Payment by Result|Incentive earnings, the same shall be the average of such earnings earned during the 10 complete months immediately preceding the date of commencement of continuous leave.

25. The term emoluments|average emoluments in regulations 23 and 24 shall not apply for payment of Gratuity to employees governed by 'The Payment of Gratuity Act, 1972' in respect of whom Gratuity is payable in accordance with regulation 45 contained in Chapter IX in these regulations.

CHAPTER VI—AMOUNT OF PENSION

26. In respect of an employee retiring in accordance with the provisions of these regulations after completing a qualifying service of not less than 10 years, the amount of pension shall be the appropriate amount as set out below, namely :—

Completed six monthly period of qualifying service	Scale of pension	Maximum pension (in Rs. per annum) in respect of Classes I and II officers and Class III and IV employees who opt for definition of emoluments under Regu- lation 23(ii) (b) in Chapter V.	Maximum pension (in rupees per annum) in respect of Classes III and IV employees who opt for definition of emoluments under Re- gulation 23(ii) (a) in Chapter V.
(1)	(2)	(3)	(4)
20	10/80th of average emoluments.	Rs. P. 3,750.50	Rs. 2,700
21	101-2/80 -do-	3,937.50	2,335
22	11/80 -do-	4,125.00	2,970
23	11-1/2/80 -do-	4,312.50	3,105
24	12/80 -do-	4,500.00	3,240
25	121/280 -do-	4,687.50	3,375
26	13/80 -do-	4,875.00	3,510
27	13-1/2/80 -do-	5,062.50	3,645
28	14/80 -do-	5,250.00	3,780
29	14-1/2/80 -do-	5,437.50	3,915
30	15/80 -do-	5,625.00	4,050
31	15-1/2/80 -do-	5,812.50	4,185
32	16/80 -do-	6,000.00	4,320
33	16-1/2/80 -do-	6,187.50	4,455
34	17/80 -do-	6,375.00	4,590
35	17-1/2/80 -do-	6,562.00	4,725
36	18/80 -do-	6,750.00	4,860
37	18-1/2/80 -do-	6,937.00	4,995
38	19/80 -do-	7,125.00	5,130
39	19-1/2/80 -do-	7,312.50	5,265
40	20/80 -do-	7,500.00	5,400
41	20-1/2/80 -do-	7,687.50	5,535
42	21/80 -do-	7,875.00	5,670
43	21-1/2/80 -do-	8,062.50	5,805
44	22/80 -do-	8,250.00	5,940
45	22-1/2/80 -do-	8,437.50	6,075
46	23/80 -do-	8,625.00	6,210
47	23-1/2/80 -do-	8,812.50	6,345
48	24/80 -do-	9,000.00	6,480
49	24-1/2/80 -do-	9,187.50	6,615

(1)	(2)	(3)	(4)
50	25/80th of average emoluments	9,375.00	6,750
51	25-1/2/80 -do-	9,562.50	6,885
52	26/80 -do-	9,750.00	7,020
53	26-1/2/80 -do-	9,937.50	7,155
54	27/80 -do-	10,125.00	7,290
55	27-1/2/80 -do-	10,312.50	7,425
56	28/80 -do-	10,500.00	7,560
57	28-1/2/80 -do-	10,687.50	7,695
58	29/80 -do-	10,875.00	7,830
59	29-1/2/80 -do-	11,062.50	7,965
60	30/80 -do-	11,250.00	8,100
61	30-1/2/80 -do-	11,437.50	
62	31/80 -do-	11,625.00	
63	31-1/2/80 -do-	11,812.50	
64	32/80 -do-	12,000.00	
65	32-1/2/80 -do-	12,000.00	
66	33/80 -do-	12,000.00	

NOTE—(1) Notwithstanding anything contained above the amount of invalid pension shall not be less than the amount of family pension admissible under Regulation 47(i) in Chapter X.

(2) In calculation of the length of service, fractions of a year equal to six months and above shall be treated as a completed six monthly period.

(3) The amount of pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of rupee, it shall be rounded off to next higher rupee.

(4) In no case a pension in excess of the maximum pension prescribed under this regulation shall be allowed.

(5) The amount of pension shall be subject to a minimum of Rs. 40 per mensem.

(6) Where the pension including adhoc increase, if any, is less than forty rupees per mensem the difference shall be made good by the grant of further increase in pension.

27. In respect of Classes I and II, Officers and Classes III and IV employees who opt for definition of emoluments under Regulation 23(ii) (b) in Chapter V who were in service on 31st March 1979 and

retiring from service on or after that date the amount of pension shall be determined in accordance with the following slabs :

	Amount of monthly pension.
(i) Up to first Rs. 1,000 of average emoluments reckonable for pension.	50 per cent of average emoluments.
(ii) Next Rs. 500 of average emoluments reckonable for pension.	45 per cent of average emoluments.
(iii) Balance of average emoluments reckonable for pension.	40 per cent of average emoluments subject to an overall ceiling as per note (2) below.

NOTES : (1) The amount of pension arrived at on the basis of the above slabs will be related to the maximum qualifying service of 33 years. For employees who at the time of retirement, have rendered qualifying service of ten years or more but less than 33 years the amount of their pension will be such proportion of the maximum admissible pension as the qualifying service rendered by them bears to the maximum qualifying service of 33 years.

(2) The pension as determined in accordance with the above slab plus the relief linked to the All India Working Class Consumer Price Index up to Index 328 admissible under Regulation 32 (iii) and 32(iv) of Chapter VII shall not exceed Rs. 1,500 per mensem. If the pension itself exceeds Rs. 1,500 per mensem, then the maximum pension for full 33 years of service will be restricted to Rs. 1,500 per mensem and no relief will be payable up to index level 328.

28. **Service Gratuity.**—In the case of an employee retiring in accordance with the provisions of these regulations before completing a qualifying service of 10 years, the amount of service gratuity payable in lieu of pension shall be the appropriate amount as set out below, namely :—

Completed six monthly periods of qualifying service	Scale of service gratuity	
(1)	(2)	
1	1 month emoluments.	
2	1	-do-
3	1 1/2	-do-
4	2	-do-
5	2 1/2	-do-
6	3	-do-
7	3 1/2	-do-
8	4	-do-
9	4 3/8	-do-
10	4 3/4	-do-
11	5 1/8	-do-
12	5 1/2	-do-
13	5 7/8	-do-
14	6 1/4	-do-
15	6 5/8	-do-
16	7	-do-
17	7 3/8	-do-
18	7 3/4	-do-
19	8 1/8	-do-

In calculating the length of service, fractions of a year equal to six months and above shall be treated as a completed six monthly period.

CHAPTER VII—RELIEF ON PENSION] FAMILY PENSION

29. **Ad hoc Relief on Pension.**—Classes I and II Officers who retired prior to 1st January 1973 & Classes III & IV employees who retired prior to 1st January 1969 will be eligible to an ad hoc relief at the rates mentioned below with effect from 1st September 1969 (i.e. pension for the month of September 1969 paid in October 1969).

Amount of pension	Rate of ad hoc increase pension
(1)	(2)
Pension up to Rs. 30	Rs. 15 per mensem.
Pension above Rs. 30 but not above Rs. 75.	Rs. 17.50 per mensem.
Pension above Rs. 75 but not above Rs. 200.	Rs. 20 per mensem.
Pension above Rs. 200	Such ad hoc increase as to bring the total pension to Rs. 220 per mensem.

30. **Additional ad hoc relief on pension.**—Classes I and II Officers who retired prior to 1st January, 1973 and Classes III and IV employees who retired prior to 1st January 1969 will be eligible to an

additional ad hoc relief in addition to the ad hoc relief admissible under Regulation 29 above, at the rates mentioned below with effect from 1st January 1973, i.e. pension for January 1973 paid in February 1973.

Pension (Based on original pension)	Amount of ad hoc relief in pension
Below Rs. 85	Rs. 15 per mensem.
Rs. 85 and above but below Rs. 210.	Rs. 21 per mensem.
Rs. 210 and above but below Rs. 500.	Rs. 25 per mensem.
Rs. 500 and above.	Rs. 35 per mensem.

NOTE :—The term original pension including compassionate allowance for the purpose of calculation of additional ad hoc relief does not include ad hoc increase in regulation 29 above. But includes the commuted portion of pension if any.

31. **Classes III and IV employees who retired between 1st January 1969 to 31st December, 1973** also will be eligible for the ad hoc relief at the rates in regulation 30 above with effect from 1st January 1979:

32. **Periodical Relief on Pension.**—Periodical Relief to pensioners based on the variation in the All India Working Class Consumer Price Index (1960=100) at the base will be granted at the rates and subject to the conditions specified below :—

(i) Classes I and II Officers who retired prior to 1st January 1974 and Classes III and IV employees who retired prior to 1st January, 1969 will be allowed periodical relief at the rate of 5 per cent of the original pension subject to a minimum of Rs. 5 and a maximum of Rs. 25 per mensem on each occasion for every 16 points increase in the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index above 200 points (1960=100) as the base with effect from 1st January 1973.

(ii) The quantum of periodical relief will be calculated on the amount which is arrived at, on the following basis :—

(a) Original pension as stated in the note under Regulation 30;

(b) Ad hoc relief where admissible under regulation 29;

(c) Additional ad hoc relief admissible under regulation 30.

(iii) Classes I and II Officers who retired on or after 1st January, 1974 will be allowed periodical relief at the rate of 5 per cent of the original pension sanctioned subject to a minimum of Rs. 5 and maximum of Rs. 25 per mensem on each occasion for every 20 points rise in the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index above 250 points (1960=100) as the base with effect from 1st January, 1974 restricting it to the Consumer Price Index point up to which it is allowed to Central Government Pensioners.

(iv) Classes III and IV employees who retired on or after 1st January, 1979 and who opt for the definition of emoluments under Regulation 23(ii) (v) in Chapter V shall be allowed periodical relief as admissible to Classes I and II Officers in sub-regulation (iii) of this regulation with effect from 1st January, 1979.

(v) Classes III and IV employees who retired between the date from 1st January, 1974 to 31st December 1978 and who are compulsorily governed by definition of pay under Regulation 23(ii) (a) in Chapter V with effect from 1st January, 1979 shall be allowed periodical relief at the rate of 4 per cent of the original pension upto the CPI Points up to which the relief is allowed by the Central Government from time to time, for its pensioners subject to a minimum of Rs. 5 and a maximum of Rs. 25 on each occasion for every 20 point increase in the 12 monthly average of All India Working Class Consumer Price Index (1960=100) as the base over and above the All India Working Class Consumer Price Index on which the employee was paid Variable Dearness Allowance at the time of his/her retirement.

(vi) Classes III and IV employees who opt for the definition of pay under regulation 23(ii)(a) in Chapter V and who retired on or after 1st January, 1979 will be allowed periodical relief at the rate and subject to the conditions prescribed in sub-regulation (vi) of this regulation.

NOTES—(1) For the purpose of periodical relief in this Regulation the term pension shall mean the pension of the compassionate allowance sanctioned inclusive of commuted portion of pension, if any.

(2) The fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest 10 paise fraction of 5 paise being rounded off to the next 10 paise.

(3) The grant of relief mentioned supra is subject to such modification as the Government of India may make in the formula and method from time to time.

33. The payment of ad hoc relief, additional ad hoc relief and periodical relief shall be suspended when a person in receipt of pension/family pension is re-employed/employed in any of the organisations such as Central or a State Government/Company/Corporation/Undertaking or Autonomous body or in a Nationalised Bank or in a Local Fund.

34. Relief on Family Pension—(i) Ad hoc Relief on Family Pension—Families of Classes I and II Officers who retired/died prior to 1st January, 1973 and Classes III and IV employees who retired/died prior to 1st January, 1960 will be allowed ad hoc relief at the rates under Regulation 30 with effect from 1st October, 1975.

(ii) Periodical Relief on Family Pension.—(a) Families of Classes I and II Officers who retired/died prior to 1st January 1974 and Classes III and IV employees who retired/died prior to 1st January, 1969 will be allowed periodical relief at the rates under Regulations 32(i) and 32(ii) with effect from 1st October, 1975.

(b) Families of Classes I & II Officers who retired/died on or after 1st January 1974 will be allowed periodical relief at the rates under Regulation 32(iii) with effect from 1st October, 1975.

(c) Families of Classes III and IV employees who retired/died on or after 1st January 1979 and opt for definition of pay under regulation 23(ii) (b) will be allowed periodical relief at the rates under Regulation 32(iii) with effect from 1st January, 1979.

(d) Families of Classes III and IV employees who retired/died between the dates from 1st January, 1974 and 31st December, 1978 and who are compulsorily governed by definition of pay under Regulation 23(ii) (a) will be allowed periodical relief at the rates under Regulation 32(v) with effect from 1st January, 1979.

(e) Families of Classes III and IV employees who retired/died on or after 1st January 1979 and opt for definition of pay under Regulation 23(ii) (a) will be allowed periodical relief at the rates under Regulation 32(v) with effect from 1st January 1979.

CHAPTER VIII—COMMUTATION OF PENSION

35. (i) An employee shall be entitled subject to the conditions hereinafter specified to commute for a lump sum payment any portion of his pension not exceeding one-third of any pension other than family pension which has been or may be granted to him under these regulations as set out in the table under this regulation.

NOTE : The compassionate allowance granted under false regulations shall be treated as pension for the purpose of commutation.

(ii) Pensioner other than an invalid pensioner can commute without prior medical examination one-third of the pension sanctioned to him at the time of superannuation/retirement within a period of one year from the date of his retirement and the commutation shall become absolute, i.e., the retired employee shall become entitled to receive the commuted value of pension on the date on which his application is received.

(iii) In respect of a pensioner applying for commutation after one year from the date of his retirement and in respect of an invalid pensioner, payment of commuted value of pension is subjected to medical examination. The procedure for payment of the command value in such cases is as set out below.

On receipt of an application for commutation the sanctioning authority shall transmit to the applicant a copy of Accounts Officer's Certificate of the lump sum payable on commutation in the event of his being reported by such medical authority as the sanctioning authority may prescribe to be a fit subject for commutation and shall at the same time instruct him to appear for examination before the said authority within three months from the date of its order or if he has applied for commutation in advance of the date of his retirement within three

months of that date, but in no case earlier than the actual date of retirement. This intimation shall constitute administrative sanction for commutation, but shall lapse if the medical examination does not take place within the period prescribed in the sanctioning order. If the applicant does not appear for examination before the said medical authority, within the prescribed period the sanctioning authority may, at his discretion, renew administrative sanction for a further period of three months without obtaining a fresh application for the commutation of pension. The applicant may withdraw his application by a written notice despatched at any time before medical examination is due to take place, but this option shall expire on his appearance before a medical authority.

Provided that if the medical authority directs that his age for the purpose of commutation shall be assumed to be greater than his actual age, the applicant may withdraw his application by written notice despatched within two weeks from the date on which he receives if this sum is already stated in the sanctioning order, within two weeks from the date on which he receives intimation of the finding of the medical authority.

NOTES : (1) If the applicant does not withdraw in writing his application within the period of two weeks prescribed above, he shall be deemed to have accepted the sum offered.

(2) Subject to the foregoing provisions of this regulation the commutation shall become absolute and the title to receive the commuted portion of the pension shall cease and the title to receive the commuted value shall accrue, on the date on which the medical authority signs the medical certificate. Payment of the commuted value shall be made as expeditiously as possible, but in the case of an impaired life no payment shall be made until either a written acceptance of the commutation has been received or the period within which the application for the commutation may be withdrawn has expired. Whatever the date of actual payment, the amount paid and the effect upon the pension shall be the same as if the commuted value were paid on the date on which the commutation became absolute. If the commuted portion of the pension has been drawn after the date on which the commutation became absolute the amount drawn shall be deducted from the amount payable in commutation.

(3) If the applicant makes any statement found to be false within his knowledge or wilfully suppressed any material fact in answer to any question, written or oral put to him in connection with medical examination the sanctioning authority may cancel the sanction at any time before payment is actually made and such a statement or suppression may be treated as a grave misconduct.

(4) A pensioner after he has once been refused commutation on medical grounds or after he has once declined to accept commutation on the basis of an

addition of years to his actual age, may apply for a second medical examination at his own expense if at least a year has elapsed since his first, such a re-examination shall invariably be made by a Medical Board.

36. Calculation of lump sum payable on commutation—The lumpsum payable on commutation shall be calculated in accordance with a table or tables of present values which shall be prescribed by the Central Government from time to time in their Civil Service Regulations. The table of present values is given at Table under this Regulation. In the event of the table values applicable to an applicant having been modified between the date of administrative sanction to commutation and the date on which commutation is due to become absolute payment shall be made in accordance with the modified table, but it shall be open to the applicant if the modified table, is less favourable to him than that previously in force to withdraw his application by notice in writing despatched within 14 days of the date on which he receives notice of the modification.

37. Payment of commutation value when pensioner dies—If the pensioner dies on or after the day on which commutation became absolute but before receiving the commutation value, this value shall be paid to his heirs.

38. The authority competent to sanction commutation of pension are as under :—

- (i) Chairman in respect of Class I Officers;
- (ii) Deputy Chairman in respect of Class II Officers;
- (iii) Accounts Officer in respect of Classes III and IV employees.

39. The form of application, procedure for medical examination and payment of commuted value shall be such as may be prescribed by the Chairman from time to time.

NOTES—(1) If pension has been reduced under Regulation in Chapter XII the commutation of pension will be admissible only on such reduced pension provided the reduction in pension is permanent.

(2) The reduction in the amount of pension on account of commutation shall be effective from the date of receipt of the commuted value of pension by the pensioner or three months after the issue of the intimation authorising the pensioner to collect the Commuted value of pension whichever is earlier.

COMMUTATION TABLE

(Vide Regulation 35)

(Commutation value of a pension of Re. 1 per annum)

Age next Birthday	Commutation value expressed as number of years purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of years purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of years purchase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.53
23	18.80	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	14.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30
27	18.21	50	13.25	73	6.01
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	53	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.40	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.46	82	3.72
37	16.52	60	10.13	83	3.52
38	16.31	61	9.81	82	3.32
39	16.09	62	9.48	85	3.13

Note :—This table is based on a rate of interest at 4.75 per cent per annum

CHAPTER IX—GRATUITY

Payment of gratuity to Classes I and II Officers and Classes III and IV employees not governed by the Payment of Gratuity Act, 1972.

40. Death-cum-Retirement Gratuity—(i) An employee to whom the 'Payment of Gratuity Act, 1972' does not apply and who has completed five years of qualifying service and has become eligible for service gratuity under regulation 28 or pension under regulation 26 or 27 shall on his retirement be granted death-cum-retirement gratuity equal to one-fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of—

(a) Fifteen times the emoluments in respect of Classes III and IV employees who opt for the definition of emoluments under Regulation 23(ii)(a) :

(b) Sixteen and half times the emoluments in all other cases :

Provided that in respect of employees retiring after 4th January, 1981 and employed on a post covered by Payment by Results Schemes|Piece Rate Schemes|Premium Schemes is offered a job where he will not be eligible to any payment under such

scheme or where a worker is reverted to a lower scale, on account of any medical disability, accident, etc., the Gratuity where beneficial will be computed in two parts (viz.) :

(a) Gratuity, determined on the emoluments payable at the time of such reversion or assignment to time rated job, for the service rendered up to that date, and

(b) Additional Gratuity determined on the emoluments last payable, at the time of termination of employment for the service rendered after such reversion or assignment to time rated job.

(ii) If an employee to whom the "Payment of Gratuity Act, 1972" does not apply dies while in service after completing five years of qualifying service, the amount of death-cum-retirement gratuity shall be equal to twelve times of his emoluments or the amount determined under Sub-Regulation (i) whichever is higher and it shall be paid to his family in the manner indicated in Chapter XI :

Provided that the amount of death-cum-retirement Gratuity payable under this regulations, shall in no case exceed—

(a) Rs. 24,000 in respect of Classes III and IV employees who opt to be governed by the definition of emoluments under Regulation 23(ii) (a) ;

(b) Rs. 30,000 in all other cases :

(iii) If an employee to whom the "Payment of Gratuity Act, 1972" does not apply dies after completing one year of qualifying service but before completing five years of qualifying service, the amount of death-cum-retirement gratuity shall be equal to six times of his emoluments.

(iv) If an employee to whom the "Payment of Gratuity Act, 1972" does not apply dies in the first year of his qualifying service the amount of death-cum-retirement gratuity shall be equal to two times of his emoluments at the time of his death.

(v) If an employee dies while in service gratuity amount may be paid to the person or persons on whom the right to receive gratuity is conferred under regulation 50 or if there is no such person, it may be paid in the manner indicated below :

(a) If there are one or more surviving members of the family as in items (i), (ii), (iii) and (iv) of regulation 50, it may be paid to all such members except to a widowed daughter in equal shares.

(b) If there are no such surviving members of the family as at (a) above but there are one or more surviving widowed daughters and/or one or more surviving members of the family as in items (v) to (ix) of regulation 50 the gratuity may be paid to all such members in equal shares.

Note : With effect from 11th July, 1979, interest may be allowed on delayed payments of gratuity at the rate of 5 per cent for the period beyond three months after the gratuity becomes due and would be payable till the end of the month preceding the month in which the payment is actually made. The interest will be allowed only where it is clearly established that the payment of Death-cum-Retirement Gratuity was delayed on account of administrative lapse or for reasons beyond the control of the employees concerned. In all cases where interest has to be paid action should be taken to fix responsibility for the delay and disciplinary action should be taken against the officer responsible for it.

41. Residuary Gratuity.—If an employee to whom the 'Payment of Gratuity Act, 1972' does not apply and who has become eligible for pension or service gratuity, dies within five years from the date of his retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sum actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension including ad hoc increase, if any, together with the death-cum-retirement gratuity admissible under regulation 40 and the commuted value of any portion of pension commuted by him are less than the amount equal to twelve times his emoluments a residuary gratuity equal to the deficiency may be granted to his family in the manner indicated in Chapter XI.

42. Emoluments for the purpose of gratuity admissible under this regulation shall be subject to maximum of :—

(i) Rs. 1800 per mensem in respect of Classes III and IV employees who opt for emoluments under Regulation 23(ii) (a);

(ii) Rs. 2,500 per mensem in other cases ;

Provided that if the emoluments of an employee have been reduced during the last three years of service otherwise than as penalty, average, emoluments as referred to in Regulation 24 may, at the discretion of the authority which has power to sanction gratuity be treated as emoluments.

43. Lapse of death-cum-retirement gratuity.—

(i) leaves behind no family; or

(ii) has made no nomination; or

(iii) the nomination made by him does not subsist;

When an employee dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and the amount of death-cum-retirement gratuity payable to him under regulation 40 shall lapse to the Board.

44 (i) Payment of Gratuity to temporary employees—A temporary employee to whom The Payment of Gratuity Act, 1972 does not apply and who retires on super-annuation or is discharged from service on account of retrenchment or is declared invalid for further service shall be eligible for a gratuity at the rate of one half of emoluments for each completed year of his service. Provided that he had completed not less than five years of continuous service at the time of retirement, discharge or invalidation.

Provided that in respect of employees retiring after 4th January, 1981 and employed on a post covered by Payment by results schemes/Piece Rate Schemes/Premium Schemes is offered a job where he will not be eligible to any payment under such scheme, or where a worker is reverted to a lower scale, on account of any medical disability, accident, etc., the gratuity where beneficial will be computed in two parts. (viz) :—

(a) Gratuity, determined on the emoluments payable at the time of such reversion or assignment to time rated job, for the service rendered up to that date, and

(b) Additional gratuity determined on the wages last payable at the time of termination of employment for the service rendered after such reversion or assignment to time rated job.

(ii) The family of a temporary employee to whom The Payment of Gratuity Act, 1972 does not apply dies while in service, shall be eligible for a death gratuity on the scale and subject to the conditions specified below :—

- (a) On death after completion of one year of service, but before completion of three years' service a gratuity equal to one month's emoluments;
- (b) on death after completion of three years of service, but before completion of five years of service, a gratuity equal to two month's emoluments;
- (c) on death after completion of five years of service but before 10 years of service, a gratuity equal to three month's emoluments or the amount of gratuity as calculated under sub-regulation (i) above, if it is greater;

(iii) A temporary employee to whom 'The Payment of Gratuity Act, 1972 does not apply dies while in service or retires or is discharged for reasons other than by way of disciplinary measures or resignation after rendering a continuous service of not less than 10 years shall be eligible for a gratuity at the rate of one month's emoluments for each completed year of service subject to the following maximum :

(a) In case of death, 15 months emoluments or Rs. 15,000 whichever is less;

(b) in other cases Rs. 15,000

(iv) The grant of gratuity under this Regulation does not debar a person from the benefits of the Family Pension Scheme under Chapter X if otherwise eligible.

(v) The grant of gratuity under the above regulation shall be subject to the service rendered by the employee concerned being held by the authority competent to appoint him to be satisfactory.

(vi) No gratuity will be admissible—

- (a) In a case where the employee concerned resigns his post or is removed/dismissed from Trust's service;
- (b) to a probationer or other employee discharged for failure to pass the prescribed test or examination; and
- (c) to a re-employed pensioner.

(viii) An employee who has received gratuity under this regulation will cease to be eligible for any other gratuity or pensionary benefit.

45. Payment of Gratuity to employees governed by 'The Payment of Gratuity Act, 1972 and the Rules framed thereunder' (i) In respect of employees to whom the 'Payment of Gratuity Act, 1972' applies shall be eligible for gratuity in accordance with the provisions of the 'Payment of Gratuity Act, 1972' (Act XXX of 1972) and rules framed thereunder from time to time subject to the following liberalisation.

(ii) Wages for the purpose of computing gratuity shall include pay as defined under F. R. 9 (21) Dearness Allowance including Additional Dearness Allowance, Piece Rate earning, Incentive earnings and other such payments under a payment by Results Scheme wherever applicable, Provided that in respect of categories governed by Piece Rate, Incentive and Payment by Result Scheme wages shall be computed on the average of total wages received by them for a period 3 months or 10 months immediately preceding the termination of employment whichever is beneficial.

Note:— (1) The Special Fixed Allowance payable from 1st January 1980 to classes III and IV employees under the wage settlement, dated 4th January 1981 will be reckoned as pay :

(2) If an employee immediately before retirement or death while in service had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended, had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be the emoluments for the purpose of this regulation :

Provided that any increase in pay either on account of increment of otherwise not accruing during the first 120 days of earned leave preparatory to retirement shall not form part of his emoluments :

(iii) (a) In respect of employees who die while in service after completing five years on continuous service, the amount of Gratuity payable shall not be less than twelve months wages;

(b) If an employee dies after completing one year of service but before completing five years of service the amount of Gratuity shall be equal to six months wages :

(c) If an employee dies in the first year of his service the amount of gratuity payable shall be two months wages.

(iv) The disbursement of Gratuity payable under this Regulations the manner of filing nominations etc shall be as prescribed under the 'The Payment of Gratuity Act, 1972' and the rules framed thereunder.

(v) Residuary Gratuity.—If an employee to whom 'The Payment of Gratuity Act, 1972 applies and who has become eligible for pension or service gratuity dies within five years from the date of this retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension including adhoc increase, if any, together with the gratuity admissible under this regulation and the committed value of any portion of pension committed by him are less than the amount equal to twelve times emoluments a residuary gratuity equal to the deficiency may be granted to his family.

Chapter X—FAMILY PENSION

46. (i) In respect of an employee governed by Pension Scheme Family Pension at the prescribed rates is payable.

(a) to the family of an employee who dies while in service after completing a continuous service of not less than one year;

(b) to the family of an employee in receipt of a pension including compassionate allowance who dies after retirement.

(ii) Family for the purpose of this rule shall mean and include—

(a) wife in the case of a male employee of husband in the case of female employee provided in all these cases the marriage took place before the retirement of the employee ;

(b) wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband;

(c) son including legally adopted son who has not attained the age of 21 years and unmarried daughter including legally adopted unmarried daughter who has not attained the age of 24 years.

NOTE :—The above provision shall not include son/daughter born after retirement.

47. Rates of Family Pension.— (i) The rates of family pension admissible to the family of an employee in the event of death while in service or in the case of death after retirement shall be as under :—

(a) In respect of Classes I and II Officers and Classes III and IV employees who opt for definition of pay under regulation 23(ii) (b)

Emoluments of the employee	Amount of monthly family Pension
Below Rs. 1400	30 per cent of emoluments subject to a minimum of Rs. 60 and a maximum of Rs. 100.
Rs. 400 and above but below Rs. 1200	15 per cent of emoluments subject to a minimum of Rs. 100 and a maximum of Rs. 160.
Rs. 1200 and above	12 per cent of the emoluments subject to a minimum of Rs. 160 and maximum of Rs. 250.

NOTE :—Emoluments for the purpose of calculation of family pension for the above rates would mean pay as defined under regulation 23 (ii) (a).

(b) In respect of Classes III and IV employees who opt for definition of pay under 23(ii)(a).

308GI/87—5

Emoluments of the employee	Amount of monthly family Pension
Below Rs. 400	Rs. 60
Rs. 400 and above but below Rs. 800	Rs. 100
Rs. 800 and above but below Rs. 1200	12 per cent of pay subject to a minimum of Rs. 100.
Rs. 1200 and above	Rs. 160.

NOTE: Emoluments for the purpose of calculation of family pension would mean pay as defined under regulation 23 (ii) (a).

(ii) Death while in service (a) Where an employee who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 or who has not received any compensation for death analogous to that payable under the provisions of the Workmen's Compensation Act, dies while in service after having rendered not less than seven years of continuous service the rate of family pension payable to the family would be equal to 50 per cent of the emoluments last drawn or twice the family pension admissible at the rates indicated under Sub-Regulation (i) above whichever is less and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of 7 years or for a period up to the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived whichever is earlier.

(b) Where an employee is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 or who is entitled to compensation analogous to that under the said Act, dies while in service after having rendered not less than 7 years of continuous service the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50 per cent of the emoluments last drawn or one and half times the family pension admissible under Sub-Regulation (i) above whichever is less and the family pension so determined shall be payable for the period mention in Clause (a) above.

NOTE—(1) Where a compensation is not payable under the aforesaid Act, even in respect of an employee governed by the Workmen's Compensation Act, the rate of family pension will be as indicated in Sub-Regulation (ii) (a) above.

(2) Pay for the purpose of 50 per cent of emoluments last drawn under Sub-Regulation (ii) (a) (b) above would mean pay as defined under regulation 23 (ii) (b).

(iii) Death after retirement.—In the event of death of an employee after retirement the family pension as determined under Sub-Regulation (ii) (a) shall be payable for a period of seven years or for a period up to the date on which the retired deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived whichever is earlier.

Provided that in no case the amount of family pension determined under this Clause shall exceed the pension sanctioned on retirement of the said

employee. Provided further, the amount of family pension admissible in all these cases is subject to the minimum rate of family pension indicated in Sub-Regulation (i) above.

(iv) After the expiry of the period for payment of enhanced rate of family pension as under Sub-Regulations above as the case may be, the family in receipt of family pension shall be entitled to the family pension at the rate admissible under Sub-Regulation (i).

NOTE:—(1) In the case of an employee who dies while on extension of service, the date upto which the extension of service had been granted to him before his death will be deemed to be normal date of his superannuation.

(2) The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee. Provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under this regulation shall be allowed.

(3) The roundings off the amount of family pension has to be done at the final stage, i.e. after doubling amount initially calculated.

48. The period for which family pension is payable shall be as follows :—

(i) In the case of a widow or widower upto the date of death or remarriage whichever is earlier.

(ii) In the case of son until he attains the age of 22 years and in the case of unmarried daughter, until she attains the age of 24 years or gets married whichever is earlier.

(iii) In the case of both wife and husband are employed in the Port Trust and are governed by this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband on wife and in the event of the death of the husband and wife the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below, namely :—

(a) if the surviving child or children is/are eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in Regulation 4(ii) and 4(III) the amount of both the pension shall be limited to five hundred rupees per mensem;

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rate mentioned in Regulation 47(ii) and (III) in lieu thereof the pension at the rate mentioned in regulation 47(i) becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to five hundred rupees per mensem;

(c) if both the family pensions are payable at the rates mentioned in regulation 47(i) the amount of the two pensions shall be limited to two hundred and fifty rupees per mensem.

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 21 years in the case of the son and 24 years in the case of the daughter, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely :—

(i) if such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out below :

(ii) if there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the following order, namely :—

firstly to the son, and if there are more than one son the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder; secondly to the daughter, and if there are more than one daughter, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder.

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the sanctioning authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a Medical Officer not below the rank of a Civil Surgeon setting out, as far as possible, the exact mental or physical conditions of the child.

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter shall produce every three years a certificate from a Medical Officer not below the rank of a Civil Surgeon to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

Explanations—(1) Only that disability which manifests itself before the retirement or death of the employee while in service shall be taken into account for the purpose of grant of family pension under this regulation.

(2) A daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married.

(3) The family pension payable to such a son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his/her livelihood.

(4) In such cases it shall be the duty of the guardian to furnish a certificate every month that (a) he or she has not started earning his/her livelihood;

(b) In case of daughter, that she has not yet married.

NOTES: (1) Where an employee is survived by more than one widow, the pension will be paid to them in equal shares. On the death of a widow, her share of the pension will become payable to her eligible minor child. If at the time of her death a widow leaves no eligible minor child the payment of her share of pension will cease.

(2) Where an employee survived by a widow, but has left behind an eligible minor child from another wife, the eligible minor child will be held the share of pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee.

(3) Except as provided in the notes (1) and (2) pension awarded under this regulation shall not be payable to more than one member of an employee's family at the same time. It will first be admissible to the widow/widower and thereafter to the minor children.

(4) If sons and unmarried daughters are alive unmarried daughters will not be eligible for family pension unless the sons attain the age of 21 years and thereby become eligible for the grant of family pension.

(5) Where a deceased employee or pensioner leaves behind more children than one the eldest eligible child shall be entitled to the family pension up to the age of 21 years in respect of sons and 24 years in respect of unmarried daughters as the case may be and after the expiry of that period the next child shall become eligible for the grant of family pension.

(6) In the event of re-marriage or death of the widow, widower, the pension will be granted to the minor children through their natural guardian, if any other wise through their defacto guardian on production of indemnity bonds etc. on the analogy of the orders contained in the Ministry of Finance, Government of India O.M. No. F. 10 (3) EV (A) 61, dated the 29th June, 1961. In disputed cases, however, payments will be made through a legal guardian, i.e. guardian appointed by a Court of Law in accordance with the instructions contained in the said O. M.

(7) A judicially separated wife/husband does not lose her/his legal status of wife/husband of the employee and is thus eligible for the benefit of the family pension.

49. **Furnishing of family details**—All employees entitled to the benefits of these regulations shall furnish details of their family as defined in sub-regulation (ii) or regulation 46 i.e. the date of birth of each member with his/her relationship with the employee in the form as may be prescribed. The statement shall be countersigned by the head of the department and pasted in the service book of the employee. The employee shall thereafter keep the statement up-to-date. Additions and alterations in the statement will be made by an officer of the concerned department authorised in this behalf from time to

time on receipt of information with supporting documents from the employee concerned.

Note—(1) Effect of commutation of pension on the quantum of Family Pension—

The commutation of pension has no effect on the quantum of family pension as the rate of family pension is based on the pay which the employee was drawing immediately before his retirement and not on the pension sanctioned to him.

(2) **Broken periods of service for determining the eligibility for family pension**—

The term one year of service occurring under these regulations does not include broken periods of service. The service for the purpose should be continuous.

CHAPTER XI—NOMINATIONS

50. The provisions contained in this Chapter relating to nomination will apply in respect of employees to whom 'The Payment of Gratuity Act, 1972' does not apply.

Family

For the purpose of this regulation, family in relation to an employee means —

(i) Wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male employee;

(ii) husband, including judicially separated husband in the case of a female employee;

(iii) sons including step sons and adopted sons;

(iv) unmarried daughters including step daughters and to adopted daughters;

(v) Father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(vi) Mother including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption;

(vii) Brothers below the age of eighteen years including step brothers;

(viii) Unmarried sisters and widowed sisters including step sisters;

(ix) Married daughters; and

(x) Children of predeceased son.

Nominations

5. (i) An employee shall on his initial confirmations in a service or a post make a nomination in the appropriate form as may be prescribed, conferring on one or more persons the right to receive the death-cum-retirement gratuity payable under regulation 40;

Provided that if at the time of making the nomination—

(a) the employee has a family the nomination shall not be in favour of a person or persons other than the members of his family; or

(b) The employee has no family, the nomination may be made in favour of a person or persons or a body of individuals whether incorporated or not.

(ii) If an employee nominates more than one person under sub-regulation (i) he shall specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominee in such manner as to cover the entire amount of gratuity.

(iii) An employee may provide in the nomination—

(a) that in respect of any specified nominee who pre-deceased the employee or who dies after the death of the employee but before receiving the payment of gratuity, right conferred on that nominee shall pass to such other persons as may be specified in the nomination;

Provided that if at the time of making the nomination the employee has a family consisting of more than one member, the persons so specified shall not be a person other than a member of his family.

Provided further that where an employee has only one member in his family and a nomination has been made in his favour it is open to the employee to nominate alternate nominee or nominees in favour of any person or a body of individuals, whether incorporated or not.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of the contingency provided therein.

(iv) The nomination made by an employee who has no family at the time of making it, or the nomination made by an employee under the second proviso to clause (a) of sub-regulation (iii) where he has only one member in his family shall become invalid in the event of the employee subsequently acquiring a family or an additional member in the family as the case may be.

(v) An employee may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer provided he shall along with such notice send a fresh nomination made in accordance with this regulation.

(vi) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation (iii) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination become invalid in pursuance of clause (b) of that sub-regulation, the employee shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with this regulation.

(vii) Every nomination made and every notice of cancellation given by an employee under this regulation shall be sent an employee to the Accounts Officer through the Head of his Department and the Accounts Officer shall, if it is in order, accept it under his signature and date if and keep it under his custody.

(viii) Every nomination made and every notice of cancellation given by an employee shall be to the extent that it is valid take effect on the date on which it is accepted by the Accounts Officer.

CHAPTER XII—GENERAL CONDITIONS

52. Regulation of claims to pension or family pensions—(i) Any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these regulations in force at the time when an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be.

(ii) The day on which an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be, shall be treated as his last working day.

Provided that in case of employee who is retired prematurely or who retire voluntarily under the Madras Port Trust Employees' (Retirement) Regulations, the date of retirement shall be treated as a non-working day.

(ii) Pension including family pension shall be payable for the day on which its recipient dies.

(iv) Except for family pension admissible under Chapter X full pension under these regulations shall not be sanctioned unless the service rendered has been approved as satisfactory.

53. Reduction in the amount of pension for unsatisfactory service—(i) if the services rendered by an employee prior to the date of his retirement has not been satisfactory, the Chairman may be order, make reduction in the amount of pension or gratuity or both as he may think proper.

Provided that the Chairman shall, before passing an order under this sub-regulation serve or cause to be served a notice upon the person concerned specifying the reduction proposed to be made in such amount on account of his unsatisfactory service under the Board and call upon such person to submit within 15 days of the receipt of the notice or such further time as may be allowed by that authority, such representation as the person concerned may wish to make against the proposed order take into consideration the representation, if any, submitted by such person before passing such an order :

Provided further that the amount of pension shall not be reduced below the limit specified in note 5 under Regulation 26;

(ii) (a) The reduction referred to in sub-regulation (i) shall be of permanent character.

(b) The measure of reduction in the amount of pension shall be to the extent by which the employee's service as a whole has failed to reach a satisfactory standard and no attempt shall be made to equate the amount of reduction with the amount of loss caused to the Board.

(iii) The pension authorised under these regulations shall not be reduced although proof of the service having not been satisfactory may come to the notice of the Chairman subsequent to the authorisation of pension.

(iv) Nothing in this regulation shall apply :

(a) Where a part of pension has been withheld or ordered to be recovered under Regulation 56.

(b) Where Death-cum-Retirement Gratuity is admissible under Regulation 40 (ii) and to family pension payable.

(c) To effect any recovery which has the result of punishment;

(d) Where a part of pension has been reduced under Regulation 10.

54. Limitations on number of pensions.—An employee who having retired on a superannuation or retiring pension is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.

55. Pension subject to future good conduct.—(i) (a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

(b) The Chairman, may by order in writing withhold or withdraw a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of serious crime or is found guilty of grave misconduct :

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of such pension shall not be reduced below the minimum limit.

(ii) Where a pensioner is convicted of serious crime by a Court of Law, action under sub-regulation (i)(b) shall be taken in the light of the Judgment of the Court relating to such conviction;

(iii) In a case not falling under sub-regulation (i) if the authority referred to sub-regulation (i) (b) considers that the pensioner is prime facie guilty of grave misconduct it shall before passing an order under sub-regulation (i) (b)—

(a) Serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit within 15 days of the receipt of the notice or such further time not exceeding 15 days as may be allowed by the Chairman, such representation as he may wish to make against the proposal; and

(b) take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under clause (a).

(iv) An appeal against order under sub-regulation (i) (b) of this regulation shall be to the Board and the Board should pass such orders as it may deem fit on the appeal.

56. Right to withhold or withdraw Pension.—(i) The Chairman reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or any part of it, whether permanently or for a specified period, and the right of ordering the recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board, if, the Pensioner is found in departmental or judicial proceedings to have been guilty of grave misconduct or negligence during his service, including service rendered on re-employment after retirement :

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum limit permissible.

(ii) The departmental proceedings if not instituted while the employee was in service whether before his retirement or during his re-employment ;

(a) Shall not be instituted save with the sanction of the Chairman or the Board as the case may be ;

(b) Shall be in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings ; and

(c) Shall be conducted by such authority and in such place or places as the Chairman may direct, in accordance with the procedure applicable to proceedings on which the order of dismissal from service may be made.

(iii) No judicial proceedings, if not instituted while the employee was in service whether before retirement or during re-employment, shall be instituted in respect of a cause of acting which arose or in respect of an event which took place, more than four years before such institution.

Explanation.—For purpose of this regulation.—

(1) Departmental proceedings shall be deemed to have been instituted when the charges framed against the pensioner or issued to him or if the employee has been placed under suspension from an earlier date, on such date ; and

(2) Judicial proceedings shall be deemed to have been instituted.—

(i) In the case of criminal proceedings on the date on which the complaint is made or a charge sheet is submitted to the Criminal Court ; and

(ii) in the case of Civil Proceedings, on the date on which the plaint is presented or as the case may be, an application is made to the Civil Court.

(3) Where the Chairman decides not to withhold or withdrawn pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at the rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of an employee.

57. Revision of pension after sanction.—(i) Pension once sanctioned after final assessment shall not be revised to the disadvantage of the employee unless such revision becomes necessary on account of a clerical error :

Provided that no revision of pension to the disadvantage of the pensioner shall be ordered without the sanction of the Chairman if the clerical error is detected from a period of two years from the date of sanction of pension.

(ii) For the purpose of sub-regulation (i), the employee concerned shall be served with a notice requiring him to refund the excess payments of pensions within a period of two months from the date of receipt of notice by him.

(iii) In case of an employee fails to comply with the notice, the pension sanctioning authority, by order in writing direct that such excess payments shall be adjusted by short payments of pensions in future in one or more instalments as may be decided.

58. Drawal of pension.—Pension may be drawn and paid in any of the following manner as may be desired by the pensioner :—

- (i) By cash at the office of the Accounts Officer ;
- (ii) By Demand Draft/Cheque at his cost ;
- (iii) By Postal Money Order ;

Pension upto Rs. 100 shall be remitted to the pensioner at Trust's cost.

(iv) Payments through specified banks that may be notified.

59. Lapses and forfeitures.—If a pension remains undrawn for more than one year, it shall cease to be payable. If the pensioner afterwards appears, the Accounts Officer may renew his payment.

60. Payment of arrears of pension on death of a pensioner.—On the death of a pensioner payment of arrears actually due may be made to his/her heirs :

Provided that they apply within one year of death. Payment may not be made thereafter without the sanction of the Chairman.

CHAPTER XIII—MISCELLANEOUS

61. Authority competent to sanction pension.—The authority to sanction pension shall be—

- (i) The Chairman in respect of Class I Officers ;
- (ii) Deputy Chairman in respect of Class II Officers ;
- (iii) Accounts Officer in respect of Class III and IV employees.

62. The procedure for payment of pension, commutation of pension, gratuity and family pension and the forms required therefor for the purpose of these regulations shall be such as may be prescribed by Chairman from time to time.

63. (i) In applying the foregoing provisions of these regulations and in respect of matters not dealt within the said regulations the orders of Government contained in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 as amended from time to time shall be

subject to such exceptions and modifications as the Board may from time to time determine.

(ii) In case the Central Government liberalise or modify the existing benefits to their employees the question of extending such liberalisation or modification to the employees governed by these regulations subject to such conditions, exceptions and modifications as may be necessary shall be decided by the Board with the approval of Government of India.

In case such liberalisation or modifications are extended they shall take effect from the date they are made applicable to Central Government employees unless otherwise decided by the Central Government, pending formal amendment to these regulations.

64. The Board may by a resolution in writing prescribe which of the powers conferred upon the Board by these regulations may be exercised by the Chairman and/or Deputy Chairman and may alter or cancel any such resolution.

65. Ex-gratia pension.—(1) Employees who retired on Contributory Provident Fund before 1st April, 1963 after completing 20 years of continuous service and who therefore had no chance to elect for the pensionary benefits shall be granted an ex-gratia pension as below with effect from 1st January, 1967.

Pay drawn by the employee at the time of retirement.	Amount of ex-gratia pension	
	From 1st January 1967	From 1st February 1972
(1)	(2)	
	Rs. P.	Rs. P.
(a) Rs. 80 or less per mensem	15.00	25.00
(b) Above Rs. 80 upto Rs. 180 per mensem.	17.50	27.50
(c) Above Rs. 180 upto Rs. 200 per mensem.	20.00	30.00
(d) Above Rs. 200 and upto Rs. 500 per mensem.	22.50	32.50

(ii) These pensions will not be admissible to those who were dismissed/removed from service and to those who resigned from service.

(iii) With effect from 1st January, 1973, the ad hoc increase/relief granted by Government to its ex-gratia pensioners will be granted to Trust ex-gratia pensioners also with effect from the same dates and subject to the same conditions as applicable to the ex-gratia pensioners of the Government of India.

Note :—The rate of increase at the following rates has been allowed.

Pay drawn by the employee at the time of retirement.	Dates							
	1st January 1973	1st August 1973	1st January 1974	1st April 1974	1st October 1975	1st April 1977	1st September 1977	1st December 1978
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rs. 80 or less	Rs. 15	Rs. 5	Rs. 5	Rs. 5	Rs. 10	Rs. 5	Rs. 5	Rs. 5
Above Rs. 80 and upto Rs. 120	15	5	5	5	10	5	5	5
Above Rs. 130 and upto Rs. 200	15	5.50	5.50	5.50	11	5.50	5.50	5.50
Above Rs. 200 and upto Rs. 500	21	9	9	9	18	9	9	9

The procedure for the payment of the Pension will mutatis-mutandis apply for the grant and payment of Ex-gratia Pension also.

Madras Port Trust, Centenary Building

Rajaji Salai, Madras—600001.

Dated 29th April, 1987

Sd/-

Asst. Secretary,
MADRAS PORT TRUST

ASHOKE JOSHI,
CHAIRMAN

